नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 328
दि. 31.08.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

नेपाल में जलप्रलय का कहर: 768 मौतों से मचा हाहाकार, 2,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता; फिर बढ़ा भोटेकोशी नदी का जलस्तर

काठमांडू। नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ और उसके बाद पैदा हुए जलप्रलय ने भारी तबाही मचा दी है। आपदा के पांचवें दिन भी हालात सामान्य होने के बजाय लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है, जबकि 2,502 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि भोटेकोशी नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के साथ-साथ राहत और बचाव अभियान में जुटे सुरक्षाकर्मियों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के अब भी लापता होने के कारण मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि बाढ़ प्रभावित भोटेकोशी नदी का जलस्तर फिर बढ़ा है। नदी के बढ़ते जलस्तर ने पहले से तबाह इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाने की अपील की गई है। बचाव दलों को भी नदी और आसपास के क्षेत्रों में बदलती परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक जलस्तर बढ़ने और रास्तों के बाधित होने से राहत सामग्री पहुंचाने तथा लापता लोगों की तलाश में लगे दलों के सामने भी बड़ी चुनौतियां पैदा हो रही हैं। 26 अगस्त को आई इस आपदा ने नेपाल के कई हिस्सों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। अचानक आई

बाढ़ और तेज बहाव ने कई इलाकों में घरों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। कई परिवारों का संपर्क अपने परिजनों से टूट गया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रभावित इलाकों में तबाही का मंजर सामने आया और जगह-जगह से शव बरामद होने लगे। पांचवें दिन भी बचावकर्मी मलबे, नदी किनारे और प्रभावित क्षेत्रों में लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। एनडीआरआरएमए के अनुसार, अब तक आठ प्रभावित जिलों से शव बरामद किए जा चुके हैं।

नेपाल सरकार ने राहत और बचाव अभियान को तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों को मैदान में उतारा है। करीब 20 हजार सुरक्षाकर्मी बचाव और राहत कार्यों में तैनात किए गए हैं। इनमें नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल हैं। सुरक्षाकर्मी एक ओर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं तो दूसरी ओर लापता लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और कई स्थानों पर संपर्क मार्ग बाधित होने के कारण बचाव दलों को कई क्षेत्रों तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने शनिवार को बताया था कि अब तक 4,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो बाढ़ के तेज बहाव के बीच अपने घरों या अन्य स्थानों पर फंस गए थे। राहत एवं बचाव एजेंसियां हेलीकॉप्टरों की मदद से भी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। अब तक 227 विदेशी नागरिकों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाला जा चुका है। विदेशी नागरिकों के बचाव के लिए किए गए अभियान से यह भी पता चलता है कि आपदा का असर केवल स्थानीय आबादी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न देशों से नेपाल पहुंचे लोगों को भी इसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा।

इस प्राकृतिक आपदा ने नेपाल की शिक्षा व्यवस्था को भी गहरा झटका दिया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, बाढ़ प्रभावित तीन जिलों के विभिन्न स्कूलों से 238 छात्र और 18 शिक्षक भी लापता लोगों की सूची में शामिल हैं। बच्चों और शिक्षकों के लापता होने की खबर ने अभिभावकों और स्थानीय समुदायों की चिंता और बढ़ा दी है। कई परिवार लगातार अपने बच्चों और परिजनों के लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राहत एजेंसियां और सुरक्षा बल लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन कई स्थानों पर बाढ़ का पानी, मलबा और क्षतिग्रस्त रास्ते अभियान में बाधा बन रहे हैं।

इस बीच नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ की तीव्रता को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। काठमांडू स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिजास्टर स्टडीज के निदेशक बसंत राज अधिकारी ने आपदा की भयावहता को रेखांकित करते हुए कहा है कि ग्लेशियर और चट्टान के नदी में गिरने से पैदा हुए जलप्रलय की ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से पैदा हुई ऊर्जा से भी अधिक थी। प्राकृतिक आपदाओं और हिमालयी क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम का अध्ययन करने वाले अधिकारी ने कहा कि वह इस घटना से पूरी तरह हैरान नहीं हैं, लेकिन उनके शोध करियर में यह अब तक की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है।

विशेषज्ञों के इस आकलन ने हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते प्राकृतिक आपदा जोखिम को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। नेपाल भौगोलिक रूप से ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, तेज ढलान वाली नदियां और मानसूनी बारिश मिलकर अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा पैदा करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ना निचले इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

फिलहाल नेपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती लापता लोगों को ढूंढना और प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना है। 2,502 लोगों के अब भी लापता होने के कारण बचाव अभियान को जल्द रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुरक्षाबलों और राहत एजेंसियों को लगातार तलाशी अभियान चलाना पड़ रहा है। जिन इलाकों में पहुंचना मुश्किल है, वहां हवाई माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन की नजर भोटेकोशी नदी समेत अन्य जलस्रोतों के जलस्तर पर बनी हुई है।

8वें वेतन आयोग में 3.61 से 4.00 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग, न्यूनतम वेतन 65 से 72 हजार तक पहुंचने का अनुमान

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। आयोग की सिफारिशों का सबसे अधिक असर जिस मुद्दे पर पड़ने की उम्मीद है, वह फिटमेंट फैक्टर है। कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग सामने आने के बाद अब 3.61, 3.833 और 4.00 के आंकड़ों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यदि इन प्रस्तावों में से किसी को मंजूरी मिलती है तो मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये की तुलना में नए मूल वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी इनमें से किसी भी आंकड़े को अंतिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के आधार पर ही होगा।

8वें वेतन आयोग के गठन के करीब 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगियों तथा अन्य हितधारकों के साथ आयोग का परामर्श जारी है। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार के सामने रखने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में अभी प्रक्रिया पूरी होने में समय है, लेकिन कर्मचारियों के बीच संभावित वेतन वृद्धि को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं।

फिटमेंट फैक्टर को समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह मौजूदा मूल वेतन को नए वेतन ढांचे में संशोधित करने के लिए इस्तेमाल होने वाला गुणांक होता है। आसान शब्दों में कहें तो मौजूदा बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर संशोधित मूल वेतन का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि वास्तविक वेतन की गणना इससे कहीं अधिक जटिल होती है, क्योंकि नए वेतन मैट्रिक्स, महंगाई भत्ता और विभिन्न भत्तों सहित कई अन्य पहलू अंतिम वेतन को प्रभावित करते हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों का मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। इसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लागू किया गया था। इससे पहले 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.57 किया गया। इसी बदलाव के बाद न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन पहले की तुलना में काफी अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।

सर्वे ऑफ इंडिया की मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। यदि केवल इसी प्रस्ताव के आधार पर गणना की जाए और इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो 18,000 रुपये का मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर करीब 64,980 रुपये हो सकता है। यानी यह आंकड़ा लगभग 65 हजार रुपये के आसपास बैठता है। इस प्रस्ताव को कर्मचारियों के लिए मौजूदा मूल वेतन की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है।

दूसरी ओर नेशनल काउंसिल-जेसीएम स्टाफ साइड और भारत पेंशनर्स समाज की ओर से 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग किए जाने की बात सामने आई है। इस गुणांक के आधार पर 18,000 रुपये के मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन की गणना करने पर यह करीब 69 हजार रुपये तक पहुंच सकता है। यानी 3.61 के प्रस्ताव की तुलना में यह और अधिक वेतन का अनुमान प्रस्तुत करता है।

सबसे ऊंची मांग भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की ओर से 4.00 फिटमेंट फैक्टर को लेकर बताई जा रही है।

मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भारत-उज्बेकिस्तान दोस्ती को मिली नई ऊंचाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान 'ओलिय दाराजाली दोस्तलिक' से सम्मानित किया गया। ताशकंद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। उज्बेकिस्तान का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, आपसी सहयोग बढ़ाने और भारत-उज्बेकिस्तान की पारंपरिक मित्रता को नई दिशा देने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की मान्यता के तौर पर दिया गया है। यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को लगातार मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान प्राप्त करने के बाद इसे व्यक्तिगत उपलब्धि के बजाय भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि वह 'ओलिय दाराजाली दोस्तलिक' सम्मान प्राप्त कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं और इसे भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच स्थायी संबंधों को समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को दोनों देशों के लोगों के बीच साझा और गहरी जड़ों वाली मित्रता का प्रतिबिंब बताया। उनके इस संदेश से यह स्पष्ट हुआ कि भारत सरकार दोनों देशों के बीच संबंधों को केवल राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं मानती, बल्कि इन्हें साझा इतिहास, संस्कृति और लोगों के बीच मजबूत संपर्क से जोड़कर देखती है।

'ओलिय दाराजाली दोस्तलिक' उज्बेकिस्तान

का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मित्रता, सहयोग और आपसी संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मिलना भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते विश्वास और रणनीतिक नजदीकी का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, संस्कृति और संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए जाने को द्विपक्षीय रिश्तों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर ताशकंद पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा करने के साथ-साथ भविष्य में संबंधों को और व्यापक बनाने के नए रास्तों पर चर्चा की। बातचीत में आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश, क्षेत्रीय संपर्क, रक्षा एवं सुरक्षा तथा दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि भारत मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। वहीं, उज्बेकिस्तान के लिए भी भारत के साथ मजबूत संबंध आर्थिक अवसरों के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता और संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष दोनों देशों के बीच मौजूद सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध भी रहा। शनिवार को ताशकंद में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के तहत प्रधानमंत्री ने यंगी उज्बेकिस्तान पार्क में स्थित एक स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को याद किया और साझा विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त किया। भारत और मध्य एशिया के बीच सदियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क रहे हैं। रेशम मार्ग के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच व्यापार, विचारों और संस्कृति का आदान-प्रदान होता रहा है।

यात्रा में योग ने भी दोनों देशों के बीच बढ़ते जन-से-जन संबंधों को प्रदर्शित किया। ताशकंद में आयोजित विशेष योग प्रदर्शन में 52 स्थानीय योग साधकों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम उज्बेकिस्तान में भारतीय योग पद्धति की बढ़ती लोकप्रियता का उदाहरण बना।

18,600 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी की जंग, खतरनाक ढलान पर भारतीय सेना ने युवक को किया सुरक्षित रेस्क्यू

नई दिल्ली। बर्फीली चोटियों, बेहद कम तापमान, तेज पहाड़ी हवाओं और खड़ी ढलान के बीच भारतीय सेना ने एक बार फिर अपने अदम्य साहस और अद्भुत पेशेवर क्षमता का परिचय दिया है। नुन-कुन पर्वतमाला के पास करीब 18,600 फीट की ऊंचाई पर एक युवक को सुरक्षित निकालने के लिए सेना ने ऐसा चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसमें जरा-सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। बेहद ऊंचाई वाले इलाके में हवा का दबाव कम होने के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान पहले से ही कठिन थी, वहीं मरीज के आसपास लैंडिंग के लिए पर्याप्त जगह भी उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद भारतीय सेना के एविएशन विंग ने जोखिम उठाते हुए मरीज तक पहुंच बनाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

यह अभियान भारतीय सेना के लिए सिर्फ एक सामान्य मेडिकल रेस्क्यू नहीं था, बल्कि बेहद कठिन भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों में मानवीय जीवन बचाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण भी रहा। 18,600 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर कम होता है और सामान्य मैदानी इलाकों की तुलना में हेलीकॉप्टर संचालन काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तेज हवाएं उड़ान को और कठिन बना देती हैं। ऐसे हालात में पायलटों को हेलीकॉप्टर के वजन, ईंधन, ऊंचाई और हवा की गति सहित हर पहलू का बेहद सटीक आकलन करना पड़ता है।

रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए हेलीकॉप्टर का वजन कम करना सबसे

महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक था। सेना ने उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर से सभी गैर-जरूरी उपकरणों और सामान को हटा दिया। इसका उद्देश्य हेलीकॉप्टर को जितना संभव हो सके हल्का रखना था, ताकि इतनी अधिक ऊंचाई पर उसकी उठाने की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही सीमित मात्रा में ईंधन लेकर उड़ान भरी गई, जिससे हेलीकॉप्टर का कुल भार कम रखा जा सके और मरीज को निकालने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध रहे।

मिशन के दौरान मौसम और भूभाग ने भी सेना की परीक्षा ली। मरीज जिस स्थान पर फंसा था, वहां पहाड़ की ढलान बेहद खड़ी थी। आसपास ऐसी कोई समतल जगह नहीं थी, जहां हेलीकॉप्टर को सामान्य तरीके से उतारा जा सके। तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर को स्थिर रखना भी अत्यंत कठिन था। ऐसी परिस्थिति में पायलटों को न केवल हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना था, बल्कि मरीज और बचाव दल की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी थी। जब हेलीकॉप्टर मरीज के नजदीक पहुंचा तो चालक दल ने बेहद सावधानी से अपनी स्थिति बनाई। सामान्य परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए पर्याप्त समतल जमीन जरूरी होती है, लेकिन यहां ऐसा संभव नहीं था। इसके बावजूद पायलटों ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए हेलीकॉप्टर को खड़ी ढलान के पास बेहद कम ऊंचाई पर स्थिर रखा। यह स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि कुछ क्षणों के लिए हेलीकॉप्टर को केवल एक स्किड के सहारे ढलान का स्पर्श कराते हुए संतुलित किया गया।

इस तकनीकी रेस्क्यू के दौरान समय का भी विशेष महत्व था। सेना के अनुसार यह अभियान दिन की आखिरी उपलब्ध लैंडिंग विंडो के दौरान किया गया। यानी मौसम और रोशनी की स्थिति को देखते हुए बचाव दल के पास कार्रवाई के लिए सीमित समय था। यदि इस अवसर पर मिशन सफल नहीं होता, तो मरीज को सुरक्षित निकालने में और अधिक कठिनाई हो सकती थी। ऐसे में चालक दल ने उपलब्ध समय का बेहद सटीक इस्तेमाल किया और मरीज को तेजी से हेलीकॉप्टर में सुरक्षित किया।

मरीज को सुरक्षित करने के बाद हेलीकॉप्टर ने अत्यंत सावधानी से उड़ान भरी। इतनी अधिक ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर का नियंत्रण बनाए रखना सामान्य उड़ान की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।

मोहन भागवत के संदेश पर भाजपा नेताओं की एक सुर में मुहर, बोले- 'सबको साथ लेकर चलना ही भारत की पहचान'

नई दिल्ली । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम संबंधों को लेकर अमेरिका में दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने समर्थन जताया है। भाजपा नेताओं ने भागवत के बयान को भारत की सांस्कृतिक परंपरा, विविधता और समावेशी सोच से जोड़ते हुए कहा कि हिंदुत्व की मूल भावना किसी समुदाय को अलग करने की नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की है। नेताओं ने कहा कि भारत की पहचान उसकी विविधता में एकता, सह-अस्तित्व और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना से होती है। न्यूयॉर्क में आयोजित 'एक दुनिया, एक मानवता' कार्यक्रम में मोहन भागवत ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पर बात करते हुए कहा था कि भारत की पहचान 'विविधता में एकता' से है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति खुद को हिंदू मानते हुए यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रह सकता। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई और भाजपा नेताओं ने सामने आकर इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू की अवधारणा किसी एक पंथ या पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार हिंदू जीवन जीने का एक तरीका है, जिसकी मूल भावना सभी को साथ लेकर चलने की है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व में अलग-अलग पंथों, धर्मों और पूजा के विभिन्न तरीकों को मानने वाले लोगों के प्रति सम्मान की भावना है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ है या उन्हें भारत का हिस्सा नहीं मानता, तो भागवत का यह कहना उचित है कि ऐसी सोच हिंदू विचारधारा की मूल भावना से मेल नहीं खाती।

भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी मोहन

भागवत के बयान को भारत की वास्तविक सामाजिक संरचना से जोड़ते हुए कहा कि भारत में रहने वाले हर नागरिक की पूजा-पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन वह देश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की अवधारणा में मुस्लिम समुदाय को अलग-थलग या देश से बाहर मानने की कोई बात नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने 'वसुधैव कुटुंबकम' की भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश सभी समुदायों के साथ मिलकर आगे बढ़ता है।

उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की बात करते रहे हैं और संघ प्रमुख का संदेश भी इसी व्यापक सोच से जुड़ा हुआ है। शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि संघ और भाजपा के बारे में कई बार गलतफहमियां पैदा की जाती हैं, लेकिन भारत की वास्तविकता यह है कि यहां अलग-अलग समुदायों के लोग साथ रहते हैं और देश के निर्माण में योगदान देते हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रोहन गुप्ता ने कहा कि मोहन भागवत के बयान को धर्म के खिलाफ टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध से जोड़ते हुए कहा कि भारत में हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था का पालन करने का अधिकार है। उनके मुताबिक समस्या तब पैदा होती है, जब राजनीतिक दल धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत की टिप्पणी किसी धर्म विशेष के विरोध में नहीं थी, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की बात थी।

भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी ने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भागवत ने नफरत फैलाने वालों को जवाब दिया और दुनिया के सामने भारत की समृद्ध संस्कृति तथा सह-अस्तित्व की परंपरा को रखा। उनके मुताबिक भारत की मिट्टी और संस्कृति में विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ रहने की परंपरा रही है। यासिर जिलानी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पिछले दिनों से मोहन भागवत के बयान को लेकर गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और विपक्षी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि आरएसएस का विरोध करने के लिए भागवत के बयान की गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। उनके मुताबिक भारत की वास्तविक पहचान आपसी सम्मान और सामाजिक समरसता में है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन ए. सिन्हा ने भी भागवत के बयान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि कोई हिंदू भारत को 'मुस्लिम-मुक्त' देखना चाहता है तो वह हिंदू विचारधारा की मूल भावना को नहीं समझता। उन्होंने इसे आरएसएस की समावेशी सोच और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता से जोड़कर देखा।

हालांकि, इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं पर आरएसएस के प्रति कथित नफरत को लेकर राजनीतिक हमला भी किया।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि भारतीय संस्कृति की मूल भावना 'पूरा विश्व एक परिवार' की रही है। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर भेदभाव समाज और सोच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक मोहन भागवत ने जो बात कही है, वह इसी व्यापक भारतीय विचार को सामने रखती है।

भागवत के बयान के बाद भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि पार्टी इस टिप्पणी को हिंदुत्व की व्यापक और समावेशी व्याख्या के रूप में प्रस्तुत कर रही है। नेताओं का कहना है कि भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में किसी एक समुदाय को अलग करके राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके मुताबिक भारत की ताकत ही उसकी विविधता में है और विभिन्न धार्मिक समुदायों का साथ रहना देश की सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मोहन भागवत का बयान ऐसे समय में आया है जब देश में हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक पहचान और अल्पसंख्यक समुदायों की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी है। ऐसे में उनके बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं। भाजपा नेताओं ने जहां इसे भारत की समावेशी संस्कृति का संदेश बताया है, वहीं विपक्ष की ओर से इस बयान को किस राजनीतिक संदर्भ में देखा जाता है, यह आने वाले दिनों में बहस का विषय बना रह सकता है। फिलहाल भाजपा नेताओं ने एक स्वर में यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारत की पहचान किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि अनेक आस्थाओं और परंपराओं के साथ मिलकर बनी है।

संपादकीय

डरना छोड़िए जनाब, राजनीति में आए हैं तो सहना भी सीखिए!

मान्यवर! अब डरना-वरना छोड़िए। जी हां, यह कोई फिल्मी संवाद नहीं और न ही 'आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो' वाला कोई गीत है। यह तो आजकल हमारी अदालतों से मिलने वाली एक तरह की राजनीतिक सलाह है। फर्क बस इतना है कि पहले मां-बाप बच्चों से कहते थे कि मुसीबत से घबराना नहीं, शिक्षक कहते थे कि कठिनाइयों का डटकर सामना करना और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन से यह साबित किया कि डर के आगे झुकना विकल्प नहीं है। लेकिन अब लगता है कि लोकतंत्र के मैदान में उतरने वाले नेताओं को भी अदालतें यही पाठ पढ़ाने लगी हैं—भाई साहब, राजनीति में आए हैं तो थोड़ा मजबूत बनिए, हर चीज से डरिए मत! कहानी पश्चिम बंगाल की राजनीति से शुरू होती है, जहां चुनावी हार के बाद राजनीतिक माहौल पहले से ज्यादा तल्ख दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस की एक महिला सांसद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आशंका जताई कि उन पर अंडे फेंके जा सकते हैं। मामला सुनने में भले ही थोड़ा हल्का लगे, लेकिन जिस राजनीतिक माहौल का हवाला दिया गया, उसमें डर को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। आखिर राजनीति में विरोध अब केवल भाषणों और नारों तक सीमित कहां रह गया है? कभी पोस्टर फाड़े जाते हैं, कभी पुतले जलते हैं, कभी नारेबाजी होती है और कभी-कभी विरोध प्रदर्शन व्यक्तिगत हमलों की सीमा तक पहुंच जाता है। मगर अदालत का नजरिया थोड़ा अलग था। अदालत ने उन्हें मानो यह समझाने की कोशिश की कि राजनीति में रहना है तो विरोध का सामना करने का साहस भी रखना होगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां खाईं, गोलियां झेलीं, जेल गए, यातनाएं सहीं, लेकिन अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। ऐसे में अगर कोई जनप्रतिनिधि अंडे फेंके जाने की आशंका से ही परेशान हो जाए तो अदालत का यह कहना स्वाभाविक ही लगता है कि जनाब, थोड़ा हौसला रखिए। अब सवाल यह है कि अंडे ही क्यों? कभी नेताओं के विरोध में अंडे के साथ टमाटर भी खूब चलते थे। भाषण शुरू होते ही किसी को टमाटर पसंद नहीं आया तो मंच की ओर उड़ जाता था। लेकिन अब टमाटर कहां हैं? कहीं महंगाई ने विरोध की राजनीति से भी टमाटर को बाहर तो नहीं कर दिया? अंडा अभी भी राजनीतिक विरोध का हथियार बना हुआ है, मगर टमाटर शायद बाजार की ऐसी वस्तु बन चुका है जिसे फेंकने से पहले आदमी दस बार सोचता है। आखिर महंगाई ने विरोध करने वालों की जेब का भी बजट बिगाड़ दिया है। और जूतों की माला? वह भी अब पहले जैसी आम राजनीतिक भाषा नहीं रही। कभी किसी नेता के पुतले को जूतों की माला पहनाना विरोध का बड़ा चर्चित तरीका हुआ करता था। आज लगता है कि विरोध करने वालों ने भी महंगाई, कानूनी कार्रवाई और सोशल मीडिया की वायरल संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने तरीके बदल लिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब अदालत ने किसी राजनेता को इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत रहने की सलाह दी हो। इससे पहले एक भाजपा सांसद को भी सोशल मीडिया पर बनाए जा रहे मीम्स और आलोचनात्मक सामग्री को लेकर अदालत का रुख कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। राजनीतिक दल बदलने के बाद सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। उन्होंने अदालत से राहत की मांग की, लेकिन अदालत ने संकेत दिया कि राजनीति में आने के बाद सार्वजनिक आलोचना और राजनीतिक व्यंग्य का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बात बिल्कुल सीधी है। लोकतंत्र में नेता जनता के सामने खड़े होते हैं। वे वोट मांगते हैं, भाषण देते हैं, नीतियों का बचाव करते हैं, विरोधियों पर सवाल उठाते हैं और सत्ता में आने पर फैसले लेते हैं। ऐसे में जनता और विपक्ष की आलोचना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हां, आलोचना और हिंसा के बीच स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। किसी नेता पर हमला करना, नुकसान पहुंचाना या डराने-धमकाने की कोशिश को सिर्फ इसलिए जायज नहीं ठहराया जा सकता कि वह राजनीति में है। लेकिन दूसरी ओर, हर असहमति, हर मीम और हर तीखी टिप्पणी को खतरा मान लेना भी लोकतांत्रिक स्वभाव के अनुकूल नहीं कहा जा सकता।

सुविधाओं के शहरों में घटती इंसानी जगह

> एक अच्छे व्यवस्थित शहर की परख इस बात से होनी चाहिए कि क्या कोई बच्चा सुरक्षित रूप से स्कूल जा सकता है, क्या कोई बुज़ुर्ग सड़क पर उतरे बिना बाज़ार पहुंच सकता है, क्या व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बस स्टॉप तक पहुंच सकता है?

बढ़ता शहरीकरण सुविधाओं के लिहाज़ से बेहतर तो लगता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बुज़ुर्गों के टहलने, बच्चों के खेलने, दिव्यांगजनों के बाधामुक्त आवागमन और महिलाओं व आम नागरिकों के लिए पैदल चलने, घूमने व बैठने की जगहें उत्तरोत्तर सिकुड़ती जा रही हैं। परिणामस्वरूप, आए दिन बढ़ती दुर्घटनाओं और बीमारियों ने लोगों को अपने घरों तक सीमित रहने पर मजबूर कर दिया है। आज बच्चे खुले मैदानों में खेलने के बजाय मोबाइल गेम्स की तरफ़ उन्मुख हैं और महिलाएं स्क्रीन पर रील्स देखने में व्यस्त हो गई हैं। मोहल्ले की वे सड़कें, जो कभी बच्चों की किलकारियों, औरतों की बैठकों और बुज़ुर्गों की सांध्य-आवाजाही से गुलज़ार रहती थीं, आज मोटर वाहनों की चिल्ल-पों और अंधाधुंध दौड़-भाग से भयाक्रांत हो चुकी हैं।

कोर्ट ने जहां एक ओर सुरक्षित फुटपाथ देने और उन्हें बनाए रखने की सरकारी अधिकारियों की ज़िम्मेदारी निर्धारित की, वहीं दूसरी ओर उन्हें चलने योग्य, सुरक्षित व बाधामुक्त बनाने पर भी ज़ोर दिया। यह फैसला शहरी नियोजन की इस बुनियादी सोच को चुनौती देता है कि सड़कें मुख्यतः गाड़ियों के लिए होती हैं। साथ ही पैदल चलने वालों को यातायात में बाधा की तरह देखा जाता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 2024 में 36,526 पैदल चलने वालों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई, जो सड़क पर होने वाली कुल मौतों का 20.6 प्रतिशत है। इस तरह, हादसों से मरने वाले हर पांच में से एक व्यक्ति पैदल चलने वाला होता है।

अक्सर हम टूटे हुए फुटपाथ, पार्क की गई कारों, फुटपाथ पर चलती मोटरसाइकिलों, रोज़ी-रोटी कमाने की जद्दोजहद करने वाले रेहड़ी या खोमचे वालों, बिना ढके नालों और रास्ते के बीच में लगे बिज के खंभों से दो-चार होते हैं, जिनसे फुटपाथ का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है।

विदेशों में पैदल पथ, उनके दोनों ओर की हरित पट्टिकाएं, खेलते बच्चे और मज़े करते लोग शहर की ख़ूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यूरोपीय देशों में सड़कों को कारों की स्पीड के बजाय लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। सुरक्षित पैदल चलने और साइकिल चलाने के नेटवर्क, ट्रैफ़िक-शांत पड़ोस और पैदल चलने वालों के लिए बने टाउन सेंटर ने सक्रिय आवाजाही को शहरी जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बना दिया है।

पेरिस का '15-मिनट का शहर' सिद्धांत ज़रूरी सेवाओं को पैदल या साइकिल की दूरी पर रखने की कोशिश करता है। शहर ने साइकिल चलाने के बुनियादी ढांचे को काफ़ी बढ़ाया है और सैकड़ों पैदल चलने वाली स्कूल सड़कें बनाई हैं। इसका मक़सद गाड़ियों पर निर्भरता कम करना, हवा की गुणवत्ता सुधारना और रोज़ाना की शारीरिक गतिविधियों को शहरी जीवन का हिस्सा बनाना भी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षित पैदल चलने, शारीरिक सक्रियता, साफ़ हवा और सड़क सुरक्षा को स्वस्थ जीवन का आधार माना है। अगर दुनिया की आबादी ज़्यादा शारीरिक रूप से सक्रिय हो, तो हर साल 4 से 5 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है। इसलिए, सुरक्षित पैदल चलने की सहूलियत रोगों से बचाव का एक माध्यम बन जाती है। इससे ऊर्जा भी बचती है, ख़र्चा भी बचता है, प्रदूषण भी नहीं होता और सड़क पर जाम भी नहीं लगता है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस की पहल पर बैंगलोर में चर्च स्ट्रीट पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवंबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच सप्ताहांत में 750 मीटर के हिस्से को मोटर गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया और इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान, आसपास के दुकानदारों का व्यवसाय बढ़ने के साथ-साथ हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ ही, पैदल चलने वालों की संख्या में औसतन 92 से 117 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। लोगों ने वाहनों के बजाय पैदल चलना और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना शुरू किया। चर्च स्ट्रीट की सफलता यह बताती है कि जब लोगों को सुरक्षित और आकर्षक सार्वजनिक जगह मिलती है, तो वे उसका इस्तेमाल करते हैं।

शहर में वेंडिंग ज़ोन और पार्किंग स्थल नियत होने चाहिए, ताकि फुटपाथ पूरी तरह पैदल चलने वालों के लिए बचे रहें। यूटिलिटी पोल, ट्रांसफ़ॉर्मर और दूसरे बुनियादी ढांचे से फुटपाथ पर रुकावट नहीं आनी चाहिए। एक अच्छे व्यवस्थित शहर की परख इस बात से होनी चाहिए कि क्या कोई बच्चा सुरक्षित रूप से स्कूल जा सकता है, क्या कोई बुज़ुर्ग सड़क पर उतरे बिना बाज़ार पहुंच सकता है, क्या व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बस स्टॉप तक पहुंच सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून, 2026 के अपने फ़ैसले में कहा कि 'तय फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है', जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(द) के आने-जाने और जीवन की आज़ादी की संवैधानिक गारंटी से आता है। अतः 'पैदल चलने वालों के लिए ख़ास तौर पर दी गई जगह पर ट्रैफ़िक के बजाय पैदल यात्रियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।'

प्रेरणा

मोहब्बत सिर्फ याद करने का नाम नहीं, किसी के साथ निभाने का नाम भी है

श्मशान की उस खामोश दोपहर में मेरे सामने चिता सज चुकी थी। लकड़ियों के बीच मेरी मैना शांत पड़ी थी। वही मैना, जिसकी खिलखिलाहट कभी मेरे दिन की शुरुआत हुआ करती थी और जिसकी आवाज सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। आज उसके होंठ हमेशा के लिए बंद थे। मैं उसे देखे जा रहा था और भीतर से टूटता जा रहा था।

मेरे मन में बस एक ही बात घूम रही थी—अब मैं उसके बिना कैसे जिऊंगा?

कुछ ही दिन पहले की बात थी। हम दोनों एक फिल्म देखकर लौटे थे। फिल्म में नायिका की मौत के बाद नायक अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है। फिल्म देखते समय मैना ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा था, "गप्पू, अगर कभी मैं पहले चली गई तो तुम मेरी याद में जिंदगी मत खराब करना। किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना और खुश रहना।"

उस वक्त मैंने उसकी बात पर नाराज होकर अपना हाथ छुड़ा लिया था। मैंने कहा था, "तुम ऐसी मनहूस बातें क्यों करती हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता।"

वह मुस्कुराई थी। उसने मेरा हाथ फिर पकड़ लिया था और प्यार से बोली थी, "अच्छा बाबा, नाराज मत हो।"

तब मुझे क्या पता था कि उसकी कही हुई बात कुछ ही समय बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगी।

पंडित के मंत्रों की आवाज ने मुझे वर्तमान में लौटाया। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तभी मैना के पिता मेरे पास आए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने मेरे हाथ में सिंदूर की छोटी-सी डिबिया रख दी और कहा, "बेटा, इसकी मांग भर दो। इसे तुम्हारी पत्नी बनने का सपना था। आज इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो।"

मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने मैना की मांग में सिंदूर भर दिया। उसके चेहरे को आखिरी बार सहलाया। सोलह श्रृंगार में सजी वह ऐसी लग रही थी जैसे अभी आंखें खोलकर पूछ देगी, "गप्पू, ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ?"

मैंने आंखें बंद कर लीं।

काश, वक्त वहीं रुक जाता।

लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता।

मैना चली गई और मैं भीतर से खाली हो गया। कई दिनों तक मैंने ठीक से खाना नहीं खाया। पढ़ाई छोड़ दी। किसी से बात करने का मन नहीं करता था। किताब खोलता तो अक्षरों की जगह मैना का चेहरा दिखाई देता। कमरे में उसकी हंसी सुनाई देती। कभी लगता वह दरवाजे से आवाज देगी और कहेगी, "गप्पू, इतनी देर से क्या कर रहे हो?"

मेरी मां मुझे समझातीं, "बेटा, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें जीना होगा। मैना चाहती थी कि तुम कामयाब बनो।"

लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि किसी की बात मेरे दिल तक नहीं पहुंचती थी।

तब कुहू मेरे पास खड़ी रही। वह मैना की सबसे करीबी दोस्त थी और हमारे रिश्ते की हर बात जानती थी। उसने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि मैना को भूल जाओ। उसने सिर्फ इतना कहा, "उसकी याद को अपने दिल में रखो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी की दीवार मत बनने दो। अगर तुम हार गए तो मैना की याद भी दुखी होगी।"

उस दिन पहली बार मैंने किताब फिर से खोली। धीरे-धीरे पढ़ाई मेरी आदत बन गई। मैना की याद अब दर्द देने के बजाय मुझे आगे बढ़ने की ताकत देने लगी। मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने बैंकिंग और यूपीएससी दोनों परीक्षाएं पास कर लीं। बाद में मैंने भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा को अपना करियर चुना।

लोगों ने कहा कि मैं सफल हो गया हूं। लेकिन मैं जानता था कि मेरी सफलता के पीछे मेरी मेहनत के साथ एक ऐसी लड़की की याद थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी।

समय बीतता गया। परिवार वालों ने मेरी शादी की बात शुरू की। आखिरकार मैंने कुहू से शादी कर ली।

शायद यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन कुहू ने मेरे अतीत को स्वीकार कर लिया था। उसने कभी मैना से मुकाबला नहीं किया। वह बस मेरी जिंदगी को संभालती रही।

वह मेरे लिए खाना बनाती, मेरे कपड़े तैयार करती, मेरी पसंद-नापसंद याद रखती और मेरी थकान को बिना पूछे समझ जाती। मुझे कब चाय चाहिए, कौन-सा कुर्ता पहनना है, किस चीज से मेरा मूड अच्छा होगा—उसे सब मालूम था।

मैं यह सब देखता था, मगर शायद उसकी अहमियत समझ नहीं पाया था।

हमारी शादी को एक साल पूरा हो गया था। उसी दिन सुबह किसी छोटी-सी बात पर हमारा झगड़ा हो गया। बहस बढ़ी तो कुहू ने मुझसे कहा, "आप आज भी मुझे मैना की जगह नहीं दे पाए।"

मैं भी गुस्से में था। मेरे मुंह से निकल गया, "हां, मैं आज भी मैना से प्यार करता हूं।"

कुहू की आंखें भर आईं।

वह बिना कुछ कहे अपना सामान उठाकर गेस्ट रूम में चली गई।

पहले मुझे लगा, वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतता गया, उसकी कमी महसूस होने लगी। खाने की मेज पर नाश्ता रखा था, लेकिन उसमें वह अपनापन नहीं था। अलमारी में कपड़े थे, मगर किसी ने उन्हें करीने से नहीं सजाया था। बिस्तर पर सलवटें थीं और कमरे में एक अजीब-सी खामोशी थी।

तभी मुझे एहसास हुआ कि पिछले एक साल में कुहू मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरी जिंदगी की जरूरत बन चुकी थी।

मैना मेरी पहली मोहब्बत थी। उसकी याद मेरे दिल में हमेशा रहेगी। लेकिन कुहू वह थी जिसने मेरे टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ने का साहस किया था। उसने मेरे अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसी अतीत के साथ मुझे वर्तमान में जीना सिखाया था।

मैं देर तक आईने के सामने खड़ा रहा।

फिर मुझे अपनी गलती समझ में आ गई।

किसी को प्यार करने का मतलब यह नहीं कि आप उसके बाद आने वाले व्यक्ति के प्यार को कम समझें। अतीत की यादों को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में मौजूद इंसान की भावनाओं को चोट पहुंचाना प्यार नहीं है।

खेलों की उड़ान, विकसित भारत की पहचान

राष्ट्रीय खेल दिवस केवल एक महान खिलाड़ी की स्मृति को नमन करने का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र की खेल-चेतना को जगाने एवं खेल आयामों को नये शिखर देने का दिन है। 29 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिवस हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद की जयंती से जुड़ा है। खेल किसी राष्ट्र की शक्ति का केवल प्रदर्शन नहीं होते, वे उसके आत्मविश्वास, अनुशासन, सामूहिकता और वैश्विक प्रतिष्ठा के दर्पण भी होते हैं। आज जब भारत 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब खेलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ना समय की अनिवार्यता है। स्वस्थ नागरिक, अनुशासित युवा, विश्वस्तरीय खिलाड़ी और खेल-संस्कृति से संपन्न समाज-ये विकसित भारत की आधारशिलाएं हैं।29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के ऐसे जादूगर थे, जिन्होंने अपनी स्टिक से केवल गोल नहीं किए, बल्कि दुनिया के खेल मानचित्र पर भारत की पहचान अंकित की। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की स्वर्णिम सफलता में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। उनके खेल में कौशल के साथ राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और समर्पण का अद्भुत समन्वय था। उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना वास्तव में उस खेल-दर्शन को याद करना है जिसमें प्रतिभा से बड़ा परिश्रम और व्यक्तिगत उपलब्धि से बड़ा राष्ट्र का गौरव होता है। ध्यानचंद की विरासत आज के खिलाड़ियों को यह संदेश देती है कि खेल का अंतिम लक्ष्य केवल पदक नहीं, बल्कि देश के लिए सम्मान अर्जित करना है। निश्चित तौर पर खेल अब मनोरंजन नहीं, राष्ट्रीय शक्ति हैं। एक समय भारत में खेलों को पढ़ाई या रोजगार के विकल्प के रूप में गंभीरता से नहीं देखा जाता था। आज परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। क्रिकेट से आगे बढ़कर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन, हॉकी, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, शतरंज और अनेक अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण जीतकर भारतीय युवाओं को बताया कि ट्रैक और फील्ड में भी भारत विश्व विजेता बन सकता है। पी. वी. सिंधु ने बैडमिंटन में लगातार दो ओलंपिक पदक जीतकर नई पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित किया। मनु भाकर, डी. गुकेश, मीराबाई चानू, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, अवनि लेखरा, हरमनप्रीत सिंह और अनेक खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में भारतीय प्रतिभा की व्यापकता सिद्ध की है। यह बदलाव किसी एक खिलाड़ी की सफलता नहीं, बल्कि बदलती हुई राष्ट्रीय खेल-संस्कृति का संकेत है। टोक्यो 2020 में भारत ने सात पदक जीते और पेरिस 2024 में छह पदक हासिल किए। पदकों की संख्या भले ही अभी विकसित खेल राष्ट्रों के बराबर न हो, लेकिन भारतीय खेलों की चौड़ाई और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता लगातार बढ़ी है। पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो विशेष रूप से प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने यह मिथक तोड़ा है कि शारीरिक सीमाएं सफलता की सीमा निर्धारित करती हैं। भारत की वास्तविक उपलब्धि केवल पदकों में नहीं है। आज छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से निकलने वाले युवा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह खेलों के लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को राष्ट्रीय विकास और युवा सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में सामने रखा है। 'खेलो इंडिया' जैसी पहल ने विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान तथा खेल अवसंरचना के विकास को गति दी है। टॉप्स-टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से संभावित ओलंपिक पदक विजेताओं को लक्षित सहायता दी जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और विश्वविद्यालय खेलों ने युवाओं को प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराया है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, पोषण, विदेशी प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, वैज्ञानिक सहयोग और आर्थिक सहायता पर बढ़ता ध्यान इस बात का संकेत है कि खेल नीति अब केवल प्रतियोगिता आयोजित करने तक सीमित नहीं है। प्रतिभा की खोज से लेकर उसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी बनाने तक एक समग्र खेल-परिसंस्था तैयार करने की कोशिश हो रही है।

जब हम 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे, तब विकसित भारत की तस्वीर केवल ऊंची जीडीपी, आधुनिक सड़कों, अत्याधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय शहरों से पूरी नहीं होगी। विकसित भारत का वास्तविक अर्थ होगा-स्वस्थ नागरिक, ऊर्जावान युवा, मानसिक रूप से मजबूत समाज और विश्व मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा राष्ट्र। इस लक्ष्य में खेलों की भूमिका निर्णायक है। खेल युवाओं को नशे, निष्क्रिय जीवनशैली और दिशाहीनता से दूर रख सकते हैं। वे समयबद्धता, लक्ष्य-निर्धारण, हार को स्वीकार कर पुनः प्रयास करने की क्षमता और नेतृत्व सिखाते हैं। खेल मैदान लोकतंत्र की तरह हैं-यहां प्रदर्शन, अनुशासन और योग्यता ही निर्णायक होते हैं। आज देश में फिटनेस और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आर्थिक विकास तभी सार्थक होगा जब उसकी ऊर्जा स्वस्थ मानव संसाधन में परिवर्तित हो। फिट भारत ही उत्पादक भारत और शक्तिशाली भारत का आधार बन सकता है। खेलों की एक और बड़ी शक्ति है-वे सीमाओं के पार संवाद स्थापित करते हैं। मैदान में प्रतिद्वंद्वी देश आमने-सामने होते हैं, लेकिन खेल के बाद वही खिलाड़ी एक-दूसरे के अनुभव, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को समझते हैं।

अभियान

जन्माष्टमी पर कान्हा के रंग में रंगेगा दिल्ली-NCR, इन 3 भव्य मंदिरों में मिलेगा भक्ति और महाप्रसाद का अद्भुत संगम

जन्माष्टमी का त्योहार आते ही देशभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाजारों से लेकर मंदिरों तक हर तरफ कान्हा के नाम की गूंज सुनाई देने लगती है। कहीं फूलों से मंदिरों को सजाया जाता है, कहीं रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठता है तो कहीं भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की मनमोहक झांकियां सजाई जाती हैं। आधी रात को जैसे ही भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का समय होता है, मंदिरों में घंटे-घड़ियाल बजने लगते हैं और भक्त 'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की' के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना देते हैं। जन्माष्टमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के जीवन, उनकी बाल लीलाओं, प्रेम, करुणा, नीति और धर्म के संदेश को याद करने का अवसर भी है। यही वजह है कि इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने परिवार के साथ मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं। खासकर बड़े कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष सजावट, पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन, आरती, झांकी और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाती है।

अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और इस जन्माष्टमी पर परिवार के साथ किसी ऐसे मंदिर में जाना चाहते हैं, जहां आपको भव्य धार्मिक माहौल के साथ भगवान कृष्ण के दर्शन, सुंदर सजावट और प्रसाद का आनंद मिल सके, तो इस क्षेत्र में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। इनमें नोएडा का प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर, दिल्ली का श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर और गुरुग्राम का श्री श्री राधा दामोदर मंदिर खास आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।

नोएडा के सेक्टर 33 में स्थित इस्कॉन मंदिर भगवान श्रीकृष्ण के भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भक्तिमय वातावरण मन को आकर्षित करता है। यहां भगवान कृष्ण के साथ जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के भी दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर की धार्मिक सजावट और कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी तस्वीरें श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। परिवार के साथ आने वाले लोगों के लिए यह स्थान आध्यात्मिक अनुभव के साथ-साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं को करीब से समझने का अवसर भी देता है।

इस मंदिर की एक खास बात यह है कि भगवान का श्रृंगार नियमित रूप से बदला जाता है। अलग-अलग अवसरों पर भगवान को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन तो मंदिर का स्वरूप और भी आकर्षक हो जाता है। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भगवान के बाल स्वरूप की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनती है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं।

जन्माष्टमी के मौके पर यहां भजन, कीर्तन, आरती और भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़े धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जैसे-जैसे मध्यरात्रि का समय करीब आता है, भक्तों में उत्साह बढ़ता जाता है। भगवान के जन्म के समय पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठता है। श्रद्धालु इस पावन अवसर पर भगवान के दर्शन कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की कामना करते हैं।

नोएडा सेक्टर 33 स्थित मंदिर में महाप्रसाद की भी विशेष व्यवस्था रहती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को प्रसाद परोसे जाने की व्यवस्था की जाती है। जन्माष्टमी के दिन मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के लिए प्रसाद प्राप्त करना भी धार्मिक अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यहां का पता A-5, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सेक्टर 33, नोएडा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए नोएडा सेक्टर 18 और नोएडा सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन सुविधाजनक विकल्प हो सकते हैं। अगर आप नोएडा या आसपास के इलाके में रहते हैं तो जन्माष्टमी पर परिवार के साथ यहां दर्शन करने का प्लान बना सकते हैं।

दिल्ली की बात करें तो ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर भी जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण बन जाता है। आमतौर पर इसे इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर दिल्ली के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में शामिल है और पूरे साल यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जन्माष्टमी के दौरान मंदिर का वातावरण पूरी तरह कृष्णमय हो जाता है।

यहां भगवान राधा-कृष्ण के साथ सीता-राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के भी दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर की वास्तुकला, सजावट और धार्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। आरती, भजन और कीर्तन के बीच भक्त भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं।

शाम के समय होने वाली आरती इस मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में से एक होती है। जैसे ही आरती शुरू होती है, घंटियों और भजनों की आवाज पूरे परिसर को भक्तिमय बना देती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आरती में शामिल होकर भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं। जन्माष्टमी की रात मंदिर में होने वाले विशेष कार्यक्रमों का अनुभव करने के लिए दूर-दूर से भी लोग पहुंचते हैं।

मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहती है। भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद में सूजी का हलवा, पंचामृत और फूलों की माला जैसी धार्मिक सामग्री भक्तों को प्राप्त हो सकती है। भगवान को अर्पित प्रसाद को श्रद्धा के साथ ग्रहण करना भक्तों के लिए आध्यात्मिक आनंद का विषय होता है।

यह मंदिर हरे कृष्ण हिल्स, संत नगर मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित है। यहां पहुंचने के लिए नेहरू प्लेस और कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन उपयोगी विकल्प हैं। दोनों मेट्रो स्टेशन वायलेट लाइन पर स्थित हैं। दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु मेट्रो के माध्यम से आसानी से इस इलाके तक पहुंच सकते हैं।

दिल्ली-NCR में जन्माष्टमी मनाने के लिए गुरुग्राम का श्री श्री राधा दामोदर मंदिर भी एक खूबसूरत विकल्प है। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में स्थित यह मंदिर अपनी सुंदरता और वास्तुशिल्प के कारण श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर में राजस्थानी वास्तुकला की झलक दिखाई देती है और पूरा परिसर धार्मिक वातावरण से भरा हुआ महसूस होता है।

मंदिर का निर्माण मकराना मार्बल से किया गया है, जिसकी वजह से इसकी भव्यता और भी बढ़ जाती है। सफेद संगमरमर से सजा मंदिर श्रद्धालुओं के साथ-साथ वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोगों को भी आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में गोशाला और गोविंदा रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे परिवार के साथ आने वाले लोगों के लिए यह स्थान और सुविधाजनक बन जाता है।

जन्माष्टमी के अवसर पर यहां विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आरती और कीर्तन के दौरान पूरा मंदिर परिसर कृष्ण भक्ति में डूब जाता है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर में विशेष सजावट की जाती है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भक्त भगवान राधा-कृष्ण के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं।

इस मंदिर की एक और खासियत प्रसाद वितरण की व्यापक व्यवस्था है। जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। भगवान के दर्शन के बाद प्रसाद ग्रहण करना भक्तों के लिए यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है।

गुरुग्राम के सेक्टर 67 स्थित इस मंदिर तक गुरुग्राम-सोहना रोड के रास्ते पहुंचा जा सकता है। सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन से आगे स्थानीय परिवहन के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। राजीव चौक से बस के जरिए भी यहां पहुंचने का विकल्प मौजूद है।

जन्माष्टमी पर मंदिर जाने का अपना अलग ही आनंद होता है। घर में पूजा करने से लेकर मंदिर में भगवान के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने तक हर अनुभव भक्त के मन में अलग भाव पैदा करता है। खासकर बच्चों के लिए कृष्ण की झांकी, बाल गोपाल का श्रृंगार, फूलों से सजा मंदिर और भजन-कीर्तन किसी यादगार अनुभव से कम नहीं होता। परिवार के बुजुर्गों के लिए यह धार्मिक आस्था से जुड़ा अवसर होता है, जबकि युवा पीढ़ी के लिए अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का माध्यम बनता है।

हालांकि जन्माष्टमी के दिन इन मंदिरों में सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक भीड़ हो सकती है। इसलिए अगर आप दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले मंदिर के कार्यक्रम, प्रवेश व्यवस्था और समय की जानकारी अवश्य जांच लें। भीड़ के कारण पार्किंग और यातायात की समस्या भी हो सकती है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल सुविधाजनक रह सकता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

छोटी उम्र, बड़े सपने और नेतृत्व की नई उड़ान: मिलेनियम स्कूल में इंटरैक्ट क्लब की नई टीम ने संभाली कमान

सूरत। मिलेनियम स्कूल में इंटरैक्ट क्लब ऑफ टीएमएस के इंस्टॉलेशन समारोह का आयोजन उत्साह, ऊर्जा और सेवा भावना के माहौल में किया गया। रोटरी क्लब ऑफ सूरत रिवरसाइड के प्रायोजन में शुरू हुआ यह क्लब विद्यार्थियों को समाजसेवा के साथ नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का अवसर प्रदान करेगा। समारोह में विद्यार्थियों ने न केवल नई जिम्मेदारियां संभालीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करने का संकल्प भी लिया।

इंटरैक्ट रोटरी इंटरनेशनल का युवा सेवा कार्यक्रम है, जिसमें 12 से 18 वर्ष की आयु के विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को स्कूल और समाज से जुड़ी सेवा गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। इंटरैक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व, सहयोग, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और सामाजिक संवेदनशीलता जैसे गुण विकसित किए जाते हैं। वर्तमान में दुनिया के 145 देशों में 14,911 से अधिक इंटरैक्ट क्लब सक्रिय हैं और इनमें करीब 3.43 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 में भी 82 इंटरैक्ट क्लब कार्यरत हैं। ऐसे में टीएमएस में नए क्लब की शुरुआत युवा नेतृत्व और सेवा भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रोटरी क्लब ऑफ सूरत रिवरसाइड की ओर से प्रायोजित यह तीसरा इंटरैक्ट क्लब है। क्लब के औपचारिक इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन निलेश शाह ने निभाई। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि नेतृत्व करने के लिए उम्र कभी बाधा नहीं होती। उन्होंने विद्यार्थियों से आगे बढ़कर जिम्मेदारियां संभालने, नए विचारों को अपनाने और अपने आसपास सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव की शुरुआत अक्सर छोटी-छोटी पहलों से होती है और युवा इन पहलों के सबसे प्रभावी वाहक बन सकते हैं।

मिलेनियम स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका खुराना ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें जिम्मेदारी और पहल की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी बदलाव की शुरुआत स्वयं से करनी होती है।

समस्याओं पर केवल चर्चा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके समाधान का हिस्सा बनना भी जरूरी है। विद्यार्थियों को अपने विचारों को व्यवहार में उतारने और समाज के लिए उपयोगी कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

समारोह के दौरान इंटरैक्ट क्लब ऑफ टीएमएस की नई टीम ने औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां संभालीं। नीरजा रितेश घोसाल को प्रेसिडेंट, प्रेम जयेशभाई अहीर को वाइस प्रेसिडेंट और मन्नत अग्रवाल को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। संगिनी श्रीवास्तव को जॉइंट सेक्रेटरी, प्रतीक वटियानी को ट्रेजरर और सौम्या शाह तथा रिया शाह को जॉइंट ट्रेजरर बनाया गया। हर्षिता परेश वछियात को प्रेसिडेंट इलेक्ट की जिम्मेदारी दी गई।

क्लब की अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में त्विषा विहार बिजलानी को क्लब सर्विस डायरेक्टर, जान्हवी मारू को कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर, धनराज कुणाल मेहता को पब्लिक इमेज डायरेक्टर और हर्षवी जनेश पटेल को मेंबरशिप डायरेक्टर नियुक्त किया गया। नियति गोपलानी और श्री कृष्ण गुजराती को सार्जेंट-एट-आर्म्स की जिम्मेदारी मिली, जबकि त्विषा विहार बिजलानी और ध्रुवांशी आदित्य को मास्टर्स ऑफ सेरेमनी बनाया गया।

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद क्लब की प्रेसिडेंट नीरजा रितेश घोसाल ने समाजसेवा के क्षेत्र में सार्थक और उपयोगी कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इंटरैक्ट क्लब के माध्यम से विद्यार्थी केवल स्कूल स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक योगदान देने का प्रयास करेंगे। उनका उद्देश्य विद्यार्थियों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे अपने विचारों को कार्यरूप में बदल सकें और समाज के लिए कुछ उपयोगी कर सकें।

सेक्रेटरी मन्नत अग्रवाल ने क्लब के भीतर फेलोशिप, मित्रता और टीम भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरैक्ट क्लब विद्यार्थियों को एक-दूसरे से सीखने, साथ मिलकर काम करने और सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर देगा। क्लब की शुरुआती गतिविधियों में इंटर-स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना भी बनाई गई है। इस आयोजन के माध्यम से अलग-अलग स्कूलों के विद्यार्थी खेल के मैदान पर एक-दूसरे से जुड़ेंगे और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ मित्रता, सहयोग तथा टीम भावना को मजबूत करेंगे।

क्लब की गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम और कक्षा तक सीमित रखने के बजाय उन्हें वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों से जोड़ना है। समाजसेवा, खेल, टीमवर्क और नेतृत्व जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों के साथ मिलकर काम करने का आत्मविश्वास विकसित करेंगी। इससे उन्हें भविष्य में जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में भी मदद मिलेगी।

इंटरैक्ट क्लब का यह इंस्टॉलेशन समारोह इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिला। यह संदेश भी स्पष्ट रूप से सामने आया कि नेतृत्व के लिए किसी विशेष उम्र का इंतजार जरूरी नहीं है। यदि सोच सकारात्मक हो, जिम्मेदारी निभाने का साहस हो और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा हो तो छोटी उम्र में भी बड़ी पहल की जा सकती है।

मिलेनियम स्कूल में शुरू हुआ यह नया इंटरैक्ट क्लब आने वाले दिनों में विद्यार्थियों को सेवा और नेतृत्व की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में काम करेगा। क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और रचनात्मक सोच को समाजोपयोगी कार्यों में लगाने का अवसर मिलेगा। साथ ही विभिन्न स्कूलों और समुदायों के साथ जुड़कर वे सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत कर सकेंगे।

दरअसल, शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक हासिल करना नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना भी है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इंटरैक्ट क्लब विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मंच बन सकता है, जहां सेवा से संस्कार, मित्रता से रिश्ते और पहल से नेतृत्व की भावना विकसित हो। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन यदि सपने बड़े हों और उन्हें पूरा करने का जज्बा हो, तो बदलाव की शुरुआत आज से ही की जा सकती है।

जागरूक हुए सूरत के लोग, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर रख रहे नजर; एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचने पर दुकानदार पर जुर्माना

सूरत। शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और एक्सपायरी डेट को लेकर लोगों की जागरूकता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। सूरत महानगरपालिका (एसएमसी) की ओर से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, बड़े स्टोर और विभिन्न दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच तेज किए जाने के बीच अब आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संदिग्ध खाद्य सामग्री के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसकी पैकिंग, गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की जांच करने के साथ ही गड़बड़ी मिलने पर नागरिक इसकी सूचना महानगरपालिका के संबंधित विभाग तक पहुंचा रहे हैं।

पिछले कुछ दिनों में शहर में खाद्य पदार्थों से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद खाद्य सामग्री की बिक्री और गुणवत्ता को लेकर लोगों में सतर्कता और बढ़ी है। शनिवार को शहर के प्रसिद्ध कैलाश रेस्टोरेंट में काजू कतरी में फंगस मिलने का मामला सामने आया था। स्थानीय पार्षद की ओर से इसकी जानकारी तत्काल महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की गई।

इसी क्रम में रविवार को वराछा इलाके में एक्सपायरी डेट वाली कोल्ड ड्रिंक बिक्री के लिए रखे जाने का मामला सामने आया। इस मामले में एक जागरूक ग्राहक ने न केवल एक्सपायरी उत्पाद को पहचान लिया, बल्कि उसका वीडियो बनाकर महानगरपालिका के फूड डिपार्टमेंट तक शिकायत भी पहुंचाई। शिकायत के बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया।

जानकारी के अनुसार, वराछा के घनश्यामनगर की गली नंबर 20 स्थित 'जय मां खोडल' नामक कोल्ड ड्रिंक स्टॉल से एक ग्राहक ने पेय पदार्थ की

बोतल खरीदी थी। ग्राहक ने जब बोतल को ध्यान से देखा तो उस पर दर्ज एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। इसके बाद ग्राहक ने मामले को नजरअंदाज करने के बजाय इसकी जानकारी संबंधित विभाग को देने का फैसला किया। उसने पूरी स्थिति का वीडियो बनाया और सूरत महानगरपालिका के फूड डिपार्टमेंट को शिकायत भेजी।

शिकायत मिलने के बाद महानगरपालिका की टीम ने मामले की जांच की। जांच के दौरान बिक्री के लिए रखे गए उत्पाद और उससे संबंधित नियमों की पड़ताल की गई। नियमों का उल्लंघन सामने आने के बाद संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया। महानगरपालिका की कार्रवाई से यह संदेश भी गया कि खाद्य या पेय पदार्थों की बिक्री में नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जा सकती है।

दरअसल, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा केवल प्रशासन या महानगरपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें उपभोक्ताओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। बाजार से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय ग्राहक यदि पैकेट या बोतल पर लिखी निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग की स्थिति और अन्य जरूरी जानकारी की जांच करे तो कई तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। खासकर गर्मी और बदलते मौसम के दौरान पेय पदार्थों तथा जल्दी खराब होने वाले खाद्य उत्पादों को लेकर अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है।

शहर में महानगरपालिका की जांच मुहिम के साथ नागरिकों की सक्रियता बढ़ना खाद्य सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले कई बार ग्राहक खराब या संदिग्ध खाद्य सामग्री मिलने के बावजूद उसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। लोग न केवल उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग को सूचना भी दे रहे हैं।

होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, स्टॉल, सुपरमार्केट या सामान्य किराना दुकान से खाद्य सामग्री खरीदते समय ग्राहक अब पैकिंग और डेट की जानकारी को गंभीरता से देखने लगे हैं। किसी उत्पाद की पैकिंग फूली हुई हो, उसमें खराबी दिखाई दे रही हो, दुर्गंध आ रही हो या उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो तो नागरिक उसे खरीदने से बच रहे हैं। वहीं, बिक्री के लिए ऐसा सामान रखे जाने की स्थिति में इसकी सूचना प्रशासन तक पहुंचाने की पहल भी की जा रही है।

कैलाश रेस्टोरेंट में काजू कतरी में फंगस मिलने और इसके बाद वराछा में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक का मामला सामने आने से यह भी स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थों की जांच केवल बड़े प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रह सकती। छोटे स्टॉल और दुकानों पर भी यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ग्राहकों को सुरक्षित और मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थ ही उपलब्ध कराए जाएं।

महानगरपालिका की ओर से पिछले कुछ दिनों में खाद्य पदार्थों की जांच तेज किए जाने के कारण कारोबारियों में भी सतर्कता बढ़ी है। खाद्य सामग्री का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां बिक्री के लिए रखे गए उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप हों और किसी भी स्थिति में एक्सपायरी उत्पाद ग्राहकों को उपलब्ध न कराया जाए। खाद्य पदार्थों के भंडारण, बिक्री और स्वच्छता से जुड़े नियमों का पालन करना व्यापारियों की जिम्मेदारी है।

नागरिकों की बढ़ती जागरूकता का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि प्रशासन को ऐसे मामलों की जानकारी तेजी से मिल रही है। यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो ग्राहक मौके पर ही इसकी सूचना संबंधित विभाग को दे सकते हैं। वीडियो या फोटो जैसे साक्ष्य उपलब्ध होने पर जांच प्रक्रिया में भी मदद मिल सकती है। इससे छोटी सी लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को भी केवल शिकायत करने के बजाय खरीदारी के समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी पैक्ड खाद्य या पेय पदार्थ को खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखनी चाहिए। यदि डेट स्पष्ट नहीं है, पैकेज क्षतिग्रस्त है या उत्पाद की स्थिति संदिग्ध लगती है तो उसे खरीदने से बचना बेहतर है। वहीं, यदि कोई दुकानदार जानबूझकर एक्सपायरी या खराब उत्पाद बिक्री के लिए रखता है तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को देना जरूरी है।

महानगरपालिका की ओर से भी नागरिकों से अपील की जा रही है कि उन्हें कहीं भी खराब, संदिग्ध या एक्सपायरी खाद्य सामग्री की बिक्री दिखाई दे तो वे इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दें। प्रशासन और नागरिकों के बीच यह सहयोग खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सूरत जैसे तेजी से विकसित हो रहे महानगर में रोजाना लाखों लोग होटल, रेस्टोरेंट, स्टॉल और दुकानों से खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीदते हैं। ऐसे में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा का सीधा संबंध शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य से है। प्रशासन की निगरानी के साथ यदि उपभोक्ता भी जागरूक रहें तो खाद्य पदार्थों की बिक्री में लापरवाही पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है।

वराछा में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक का मामला इस बात का उदाहरण है कि एक सतर्क ग्राहक भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। ग्राहक ने बोतल की तारीख जांची, गड़बड़ी को पहचाना, उसका वीडियो बनाया और संबंधित विभाग को सूचना दी। इसके बाद महानगरपालिका ने कार्रवाई की। ऐसे मामलों में नागरिकों की सक्रियता न केवल एक व्यक्ति को संभावित नुकसान से बचाती है, बल्कि दुकानदारों और व्यापारियों को भी नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार बनाती है।

अब जरूरत इस बात की है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर यह जागरूकता केवल कुछ दिनों तक सीमित न रहे, बल्कि इसे रोजमर्रा की आदत बनाया जाए। खरीदने से पहले जांच, गड़बड़ी दिखे तो शिकायत और नियमों का पालन—इन तीनों कदमों से शहर में सुरक्षित खाद्य व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। महानगरपालिका की कार्रवाई और नागरिकों की बढ़ती जागरूकता यदि इसी तरह जारी रही तो खाद्य पदार्थों की बिक्री में होने वाली लापरवाही पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।

गंगा की लहरों ने धरा रौद्र रूप, तटवर्ती इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी; छह सेंटीमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बढ़ रहा जलस्तर

वाराणसी। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बीच गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से वाराणसी में बाढ़ का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। गंगा की लहरों ने अब रौद्र रूप लेना शुरू कर दिया है और नदी का पानी घाटों से आगे बढ़कर तटवर्ती इलाकों तथा निचली बस्तियों तक पहुंचने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के राजघाट गेज के अनुसार रविवार सुबह 10 बजे गंगा का जलस्तर 69.06 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर करीब छह सेंटीमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। ऐसे में प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है।

गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरे का निशान 71.26 मीटर निर्धारित है। वर्तमान जलस्तर अभी चेतावनी बिंदु से नीचे है, लेकिन जिस तेजी से नदी का पानी बढ़ रहा है, उससे आने वाले घंटों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज और मीरजापुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने का असर वाराणसी में दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि अगले 24 घंटे तक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ सकता है।

जलस्तर में वृद्धि का सबसे ज्यादा असर गंगा के किनारे स्थित घाटों और उनसे जुड़े संपर्क मार्गों पर दिखाई दे रहा है। दशाश्वमेध और अस्सी घाट के बीच संपर्क मार्ग पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। गंगा की तेज लहरें अब घाटों की ऊपरी सीढ़ियों तक पहुंचने लगी हैं। कई स्थानों पर पानी भरने के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आई है, जिसका सीधा असर घाटों से जुड़े स्थानीय कारोबारियों, दुकानदारों, नाविकों और अन्य लोगों की रोजी-रोटी पर पड़ रहा है।

गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी में बहाव भी तेज हो गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाव और स्टीमर के संचालन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी के नजदीक जाने से बचने और घाटों पर सावधानी बरतने की सलाह

दी जा रही है। खासकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने के लिए कहा गया है।

बाढ़ के बढ़ते पानी ने वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती की व्यवस्था को भी बदल दिया है। दशाश्वमेध घाट पर जहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती देखने पहुंचते हैं, वहां पानी बढ़ने के कारण अब छत पर गंगा आरती कराई जा रही है। घाट और आसपास की गलियों का संपर्क प्रभावित होने के चलते श्रद्धालुओं को पहले जैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके बावजूद आस्था का सिलसिला जारी है और लोग सुरक्षित स्थानों से मां गंगा की आरती में शामिल हो रहे हैं।

मणिकर्णिका घाट पर भी बढ़ते जलस्तर का असर पड़ा है। घाट के निचले हिस्सों में पानी पहुंचने के कारण अंतिम संस्कार और शवदाह की व्यवस्था ऊंचे प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। घाट तक पहुंचने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है।

गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ वरुणा नदी में भी पलट प्रवाह की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण वरुणा के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। कोनिया, शैलपुत्री, सरैया, अलईपुर, नक्खीघाट, ढेलवरिया, चौकाघाट और हुकुलगंज सहित कई तटवर्ती बस्तियां प्रभावित हुई हैं। इन क्षेत्रों में कई घरों के आसपास पानी जमा हो गया है और लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार ऊपर जा रहा है। कई स्थानों पर लोग अपने जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। जिन इलाकों में पानी पहले से पहुंच चुका है, वहां प्रशासन की गतिविधियां भी बढ़ाई गई हैं। संभावित खतरे को देखते हुए राहत और बचाव दलों को सतर्क रखा गया है।

गंगा के बढ़ते पानी का असर ढाब क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से ढाब क्षेत्र का सोता फिर भर गया है और पूरा इलाका टापू जैसा नजर आने लगा है। इससे वहां रहने वाले लोगों के साथ-साथ पशुपालकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना चुनौती बनता जा रहा है। पानी के कारण आने-जाने के रास्ते प्रभावित होने से दैनिक जरूरतों की सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कतें सामने आ सकती हैं।

स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ, जल पुलिस और पीएसी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव से जुड़े दलों को संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। प्रशासन की नजर लगातार गंगा और वरुणा के जलस्तर पर बनी हुई है। जलस्तर में किसी भी तरह की तेजी आने पर प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल आवश्यक कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।

बाढ़ का पानी तटवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचने के कारण स्थानीय लोगों में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार निगरानी रखने की बात कही जा रही है।

नेपाल में चार दिन से अहमदाबाद का पटेल दंपती लापता, संपर्क टूटने से परिवार की बढ़ी चिंता; बच्चों को भी नहीं मिल रही खबर

अहमदाबाद। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के बीच अहमदाबाद का एक दंपती पिछले चार दिनों से लापता बताया जा रहा है। नेपाल गए मिहिर पटेल और उनकी पत्नी किन्नरी पटेल से बीते चार दिनों से परिवार का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। लगातार कोशिशों के बावजूद दोनों से बातचीत नहीं हो पाने के कारण अहमदाबाद में रह रहे परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। परिवार के लोग दंपती के सुरक्षित होने की उम्मीद लगाए हुए हैं और उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

परिजनों के अनुसार मिहिर पटेल और किन्नरी पटेल कुछ दिन पहले नेपाल गए थे। यात्रा के दौरान दोनों से नियमित रूप से परिवार की बातचीत होती थी, लेकिन अचानक उनका संपर्क टूट गया। शुरुआत में परिवार ने इसे नेटवर्क की समस्या या यात्रा के दौरान फोन बंद होने जैसी सामान्य स्थिति माना, लेकिन जब एक के बाद एक कई घंटे और फिर दिन बीतते गए तथा दंपती से कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिजनों की चिंता गंभीर होती चली गई।

परिवार के मुताबिक दोनों से संपर्क स्थापित करने के लिए फोन पर लगातार प्रयास किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रिश्तेदारों और परिचितों के माध्यम से भी उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद फिलहाल दंपती के ठिकाने या उनकी स्थिति को लेकर परिवार के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। चार दिन से संपर्क नहीं होने के कारण परिजन किसी अनहोनी की आशंका को लेकर भी परेशान हैं।

नेपाल में इन दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में भारी बारिश, बाढ़ और नदी

के जलस्तर में वृद्धि से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियां और अन्य टीमें भी जुटी हुई हैं। ऐसे समय में किसी विदेशी नागरिक या पर्यटक से संपर्क टूटना उसके परिवार के लिए स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय बन जाता है। मिहिर और किन्नरी के मामले में भी परिवार इसी वजह से बेहद परेशान है।

परिजनों ने बताया कि मिहिर पटेल और किन्नरी पटेल के दोनों बच्चे न्यूजीलैंड में रहते हैं। माता-पिता से चार दिनों से संपर्क नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद विदेश में रह रहे बच्चों और अन्य रिश्तेदारों की चिंता भी बढ़ गई है। परिवार के सदस्य लगातार एक-दूसरे के संपर्क में हैं और नेपाल में दंपती के बारे में कोई जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

परिवार के सदस्यों का कहना है कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है जिससे यह पता चल सके कि दंपती कहां हैं या उनके साथ क्या हुआ है। परिवार ने उम्मीद जताई है कि दोनों सुरक्षित होंगे और किसी कारण से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा होगा। परिजनों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि नेपाल में मौजूदा परिस्थितियों के बीच दोनों तक संपर्क कैसे स्थापित किया जाए और उनकी स्थिति की पुष्टि कैसे हो।

मिहिर और किन्नरी के अचानक संपर्क से बाहर होने के बाद परिवार की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। शुरुआत में परिजनों को उम्मीद थी कि कुछ समय बाद फोन चालू होगा और दोनों से बातचीत हो जाएगी, लेकिन चार दिन बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलने से स्थिति गंभीर नजर आने लगी है। परिवार के लोग अपने स्तर पर उपलब्ध सभी माध्यमों से जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं।

नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के कारण कई क्षेत्रों में संचार और परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति भी सामने आई है। ऐसे में दूरदराज के इलाकों में मौजूद लोगों के मोबाइल फोन से संपर्क टूटने की संभावना रहती है। हालांकि मिहिर और किन्नरी के परिवार के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि उनका संपर्क किस वजह से टूटा है। इसी अनिश्चितता के कारण परिजनों की चिंता और बढ़ गई है।

परिवार का कहना है कि उन्हें फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है और वे दोनों के सुरक्षित होने की उम्मीद कर रहे हैं। परिजन लगातार संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मुताबिक मिहिर और किन्नरी के बारे में जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी, परिवार के अन्य सदस्यों को भी सूचित किया जाएगा।

इस घटना ने अहमदाबाद में रहने वाले दंपती के परिचितों को भी चिंतित कर दिया है। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि मिहिर और किन्नरी के बारे में जल्द से जल्द जानकारी मिलना जरूरी है। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियां सक्रिय होती हैं। परिवार को उम्मीद है कि जल्द ही दंपती से संपर्क स्थापित होगा और उनकी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

दंपती के बच्चे न्यूजीलैंड में रहते हैं, इसलिए उनके लिए यह स्थिति और अधिक कठिन हो गई है। विदेश में रहते हुए माता-पिता से लगातार चार दिनों तक संपर्क नहीं होना किसी भी परिवार के लिए बेहद तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। परिवार के सदस्य एक-दूसरे से जानकारी साझा कर रहे हैं और नेपाल से किसी सकारात्मक खबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

फिलहाल मिहिर पटेल और किन्नरी पटेल के लापता होने के मामले में परिवार की प्राथमिकता उनकी सुरक्षित जानकारी हासिल करना है। परिजनों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों जल्द सुरक्षित मिलेंगे और संपर्क टूटने की वजह भी सामने आएगी। परिवार ने लोगों से भी अपील की है कि यदि दंपती के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत परिवार या संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाए।

नेपाल में प्राकृतिक आपदा के बीच अहमदाबाद के इस दंपती से संपर्क टूटने की घटना ने एक बार फिर विदेश यात्रा के दौरान आपात परिस्थितियों में संपर्क व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल परिवार की नजर हर उस सूचना पर है, जो मिहिर और किन्नरी के बारे में कोई सुराग दे सकती है। चार दिन से जारी इंतजार के बीच परिजनों की एक ही उम्मीद है कि अगली खबर दंपती के सुरक्षित होने की हो।

लखनऊ छावनी में 101 करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत, अंग्रेजी नामों की जगह अब गूंजेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम

लखनऊ। लखनऊ छावनी में रविवार को विकास और विरासत, दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने की पहल दिखाई दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलकुशा लॉन परिसर में 101 करोड़ रुपये की लागत वाली 14 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं के जरिए छावनी क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, स्वच्छ पेयजल, महिला सशक्तीकरण और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान छावनी क्षेत्र के प्रमुख बाजारों के अंग्रेजी नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की महान विभूतियों के नाम पर रखने की घोषणा भी की गई। इस फैसले को केवल नाम परिवर्तन के बजाय इतिहास और नई पीढ़ी के बीच जुड़ाव मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी स्थान का नाम केवल पहचान का माध्यम नहीं होता, बल्कि उसके पीछे इतिहास, संस्कृति और उस समाज की स्मृतियां भी जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्र के बाजारों के नाम बदलने का उद्देश्य किसी औपचारिक प्रक्रिया को पूरा करना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को देश के उन महान व्यक्तित्वों के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर देना है, जिन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राजनाथ सिंह ने बताया कि लखनऊ छावनी के कई बाजारों के नाम अब स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय इतिहास से जुड़े महान व्यक्तित्वों के नाम पर किए गए हैं। इनमें वीरांगना ऊदा देवी, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और पूर्व प्रधानमंत्री

अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग प्रतिदिन इन नामों को देखेंगे और सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में इन महान व्यक्तित्वों के जीवन और योगदान को जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। खासतौर पर बच्चों और युवाओं के लिए यह इतिहास से जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए हजारों लोगों ने संघर्ष किया और अनेक वीरों ने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्तित्वों को केवल पुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय सार्वजनिक जीवन और रोजमर्रा की पहचान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों के नाम ऐसे महापुरुषों और वीरांगनाओं के नाम पर रखने से उनके योगदान की स्मृति जीवित रहती है। उन्होंने कहा कि नाम परिवर्तन का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

राजनाथ सिंह ने 14 विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य केवल भवन या बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नहीं है, बल्कि छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। परियोजनाओं में बच्चों की शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, स्वच्छ पेयजल, महिला सशक्तीकरण और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी माना जा सकता है जब उसका लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे।

उन्होंने छावनी क्षेत्र के आवासों से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, लोगों को अपने आवासों में आवश्यक बदलाव या निर्माण करने में आने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए अनुमति की व्यवस्था को आसान बनाने पर काम किया जा रहा है। इससे लंबे समय से आवश्यक सुधार और निर्माण का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नागरिकों की सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाना जरूरी है।

राजनाथ सिंह ने लखनऊ में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि शहर में बुनियादी ढांचे से लेकर जल आपूर्ति, शिक्षा, खेलकूद और बाढ़ नियंत्रण तक कई क्षेत्रों में काम हुआ है। उन्होंने इन कार्यों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग और मार्गदर्शन की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से विकास योजनाओं को गति मिली है और लखनऊ तेजी से आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर के रूप में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। उनके अनुसार, किसी भी राज्य में विकास के लिए सुरक्षित वातावरण बेहद जरूरी है। जब कानून-व्यवस्था मजबूत होती है तो उद्योग, निवेश, रोजगार और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति लगातार मजबूत हुई है और देश की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में पिछले वर्षों के दौरान हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था, अभाव और अराजकता का माहौल था। उनके मुताबिक, पिछले वर्षों में प्रदेश ने इन परिस्थितियों से बाहर निकलकर विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण से जुड़े कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मेट्रो के विस्तार से शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन आसान होने और यातायात के दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पांच डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं।

अडाजन में 'श्रावण बिजनेस फेयर 2026' का शुभारंभ, महिला उद्यमियों को मिला कारोबार बढ़ाने का मंच

सूरत। महिला उद्यमिता, स्थानीय कारोबार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) की ओर से अडाजन स्थित अमीधारा वाडी में दो दिवसीय 'श्रावण बिजनेस फेयर 2026' का आयोजन किया गया है। रविवार को सूरत की डिप्टी कलेक्टर मौसमीबेन पटेल ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। मेले में महिला उद्यमियों, छोटे कारोबारियों और हैंडीक्राफ्ट कलाकारों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं, जहां शहरवासियों को त्योहारी खरीदारी के साथ स्थानीय कारोबारियों के उत्पादों को देखने और खरीदने का अवसर मिल रहा है।

यह 'श्रावण बिजनेस फेयर' का तीसरा संस्करण है। इससे पहले एसजीसीसीआई की ओर से मोटा वराछा और पर्वत पाटिया क्षेत्र में इस तरह के मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिन्हें लोगों और कारोबारियों की ओर से सकारात्मक प्रतिसाद मिला था। इसी उत्साह को आगे बढ़ाते हुए इस बार अडाजन क्षेत्र को आयोजन के लिए चुना गया है। मेला 30 और 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। आयोजकों को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन के चलते बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचेंगे और स्थानीय महिला उद्यमियों तथा छोटे कारोबारियों को अपने उत्पाद बेचने के साथ नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

चैंबर अध्यक्ष अशोक जीरावाला ने कहा कि इस बार शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में श्रावण बिजनेस फेयर आयोजित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों और स्थानीय कारोबारियों को उनके अपने क्षेत्र में बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हर महिला उद्यमी के लिए अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाना आसान नहीं होता। ऐसे आयोजनों के माध्यम से उन्हें सीधे ग्राहकों से जुड़ने, अपने उत्पादों की पहचान बनाने और कारोबार का विस्तार करने का अवसर मिलता है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे स्थानीय उद्यमियों से खरीदारी कर 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को मजबूत करें।

डिप्टी कलेक्टर मौसमीबेन पटेल ने उद्घाटन अवसर पर महिला उद्यमिता को समाज की आर्थिक मजबूती से जोड़ते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जब महिलाएं व्यवसाय और बाजार के क्षेत्र में आगे आती हैं तो उसका लाभ केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे पूरे समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती मिलती है। उन्होंने महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन के लिए मंच उपलब्ध कराने को चैंबर की सराहनीय पहल बताया।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट रवि राज देसाई ने कहा कि एसजीसीसीआई की भूमिका केवल बड़ी इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है। छोटे और मध्यम उद्यमियों के साथ-साथ महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए भी संगठन लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाना होती है। बिजनेस फेयर जैसे आयोजन उन्हें सीधे बाजार से जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे मंचों से उद्यमियों को ग्राहकों की पसंद समझने, अपने उत्पादों पर प्रतिक्रिया हासिल करने और भविष्य की कारोबारी रणनीति बनाने में भी मदद मिलती है।

सूरत महानगरपालिका के पूर्व डिप्टी मेयर नीरव शाह ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। उन्होंने नए उद्यमियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि शुरुआत में कारोबार में अपेक्षित लाभ नहीं मिले तो भी निराश नहीं होना चाहिए। आज जो छोटे उद्यमी अपने उत्पादों के साथ बाजार में कदम रख रहे हैं, वही आने वाले समय में बड़े कारोबारी और उद्योगपति बन सकते हैं। इसके लिए निरंतर प्रयास, गुणवत्ता और ग्राहकों का विश्वास जरूरी है।

ऑल एग्जीबिशन के चेयरमैन मनीष कपाड़िया ने बताया कि चैंबर की ओर से भविष्य में भी विभिन्न अवसरों और त्योहारों के दौरान ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में नवरात्रि मेला, दिवाली मेला और ग्रैंड फूड फेस्टिवल जैसे बड़े आयोजनों की भी योजना है। इन आयोजनों के माध्यम से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों के कारोबारियों और उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री का अवसर देने का प्रयास किया जाएगा।

श्रावण मेला चेयरपर्सन रूपल शाह ने बताया कि इस वर्ष मेले का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। पिछले आयोजनों को मिले अच्छे प्रतिसाद के कारण कई पुराने स्टॉलधारक इस बार भी मेले से जुड़े हैं, वहीं अनेक नए उद्यमियों ने भी अपने उत्पादों के साथ भागीदारी की है। उन्होंने बताया कि इस बार मेले में त्योहारों और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग श्रेणियों के उत्पादों को शामिल किया गया है।

आगामी जन्माष्टमी को देखते हुए मेले में ठाकोरजी के लिए आकर्षक वाघा, कढ़ाई वाले झूले, कलात्मक सजावट और विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्री विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए डिजाइनर कुर्तियां, एथनिक वियर, इमिटेशन ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरीज और ड्रेस मटीरियल उपलब्ध हैं। घर को सजाने के लिए हैंडीक्राफ्ट और होम डेकोरेशन के सामान के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के गिफ्ट आर्टिकल भी यहां प्रदर्शित किए गए हैं।

खरीदारों के लिए मेले में खाने-पीने के उत्पादों की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। घर के बने स्नैक्स, विभिन्न प्रकार के नमकीन, मिठाइयां, माउथ फ्रेशनर और गिफ्ट हैंपर समेत कई उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए गए हैं। इससे मेले में आने वाले लोगों को त्योहारों की खरीदारी के साथ घरेलू खाद्य उत्पाद और उपहार सामग्री खरीदने का भी अवसर मिल रहा है।

मेले की खासियत यह है कि यहां केवल तैयार उत्पादों की बिक्री ही नहीं हो रही, बल्कि छोटे स्तर पर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाली महिलाओं और नए उद्यमियों को ग्राहकों के सामने अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिल रहा है। कई उद्यमियों के लिए ऐसे मेले नए ग्राहक बनाने और भविष्य के कारोबार के रास्ते खोलने का माध्यम बनते हैं। स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलने से शहर की उद्यमिता संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है।

एसजीसीसीआई की इस पहल के पीछे महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें अपने उत्पादों के लिए प्रत्यक्ष बाजार उपलब्ध कराने का उद्देश्य दिखाई देता है। आज के दौर में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बावजूद स्थानीय स्तर पर ग्राहकों से आमने-सामने जुड़ने का महत्व बना हुआ है। बिजनेस फेयर इसी जरूरत को पूरा करते हैं और उद्यमियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, डिजाइन और कीमत के बारे में सीधे ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर देते हैं।

उद्घाटन समारोह में स्थानीय पार्षद उर्वशी पटेल और धर्मेश वानियावाला सहित बड़ी संख्या में उद्यमी, कारोबारी और आगंतुक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जनीश पटेल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन चैंबर लेडीज विंग की चेयरपर्सन अल्पा मद्रासी ने किया। मेले के आयोजन से अडाजन क्षेत्र में त्योहारी खरीदारी का माहौल भी देखने को मिला। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन आगे भी जारी रहेंगे, ताकि महिला उद्यमियों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय कलाकारों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिल सके और सूरत में 'वोकल फॉर लोकल' तथा महिला आत्मनिर्भरता की भावना को और मजबूती मिले।

Gen Z और Gen Alpha बदलेंगे ब्यूटी मार्केट का खेल
2031 तक 42 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान

नई दिल्ली। भारत का ब्यूटी और पर्सनल केयर बाजार आने वाले वर्षों में तेजी से विस्तार करने की राह पर है। बदलती जीवनशैली, बढ़ती आय, युवाओं में व्यक्तिगत देखभाल को लेकर बढ़ती जागरूकता और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच देश का ब्यूटी एवं पर्सनल केयर उद्योग आने वाले समय में नए आकार में दिखाई दे सकता है। आदित्य बिड़ला कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में करीब 23 अरब डॉलर का भारतीय ब्यूटी और पर्सनल केयर बाजार वर्ष 2031 तक बढ़कर लगभग 42 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो महज पांच वर्षों में इस बाजार का आकार करीब दोगुना हो जाएगा। रिपोर्ट में भारतीय ब्यूटी और पर्सनल केयर उद्योग की तेज वृद्धि के पीछे कई कारण बताए गए हैं। इनमें युवा आबादी की बड़ी हिस्सेदारी, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा, नए ब्रांडों का तेजी से उभरना और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद प्रमुख हैं। अब ब्यूटी और ग्रूमिंग उत्पाद केवल आवश्यकता तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के लिए यह व्यक्तिगत पहचान, आत्मविश्वास और लाइफस्टाइल का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

भारत के ब्यूटी बाजार की संभावनाओं का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश वर्ष 2030 तक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ब्यूटी और पर्सनल केयर बाजार बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में करीब 12 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर रहने का अनुमान है। फिलहाल भारत में करीब 14 करोड़ लोग ब्यूटी और पर्सनल केयर उत्पादों की खरीदारी करते हैं। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर करीब 20 करोड़ हो सकती है। उपभोक्ताओं की संख्या में यह वृद्धि कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार तैयार करेगी।

इस बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवा पीढ़ी की रहने वाली है। खास तौर पर Gen Z और Gen Alpha आने वाले वर्षों में ब्यूटी मार्केट की दिशा तय करने वाले प्रमुख उपभोक्ता समूह बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2031 तक ब्यूटी सेक्टर में होने वाले कुल खर्च में Gen Z और Gen Alpha की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। वर्ष 2024 में यह हिस्सेदारी करीब 32 प्रतिशत थी। यानी आने वाले कुछ वर्षों में इन दोनों पीढ़ियों का प्रभाव ब्यूटी उद्योग पर काफी बढ़ने की संभावना है।

Gen Z और Gen Alpha की खरीदारी की आदतें पिछली पीढ़ियों से काफी अलग दिखाई देती हैं। ये उपभोक्ता किसी उत्पाद को खरीदने से पहले उसके बारे में ऑनलाइन जानकारी हासिल करते हैं। सोशल मीडिया पर उपलब्ध रिव्यू, कंटेंट क्रिएटर्स की राय, उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसकी गुणवत्ता और त्वचा या शरीर पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव जैसी चीजों को लेकर युवा ग्राहक अधिक सजग हो रहे हैं। यही कारण है कि कंपनियां अब केवल पारंपरिक विज्ञापनों पर निर्भर रहने के बजाय सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर भी बड़ा निवेश कर रही हैं।

सोशल मीडिया ने ब्यूटी उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री का तरीका भी बदल दिया है। किसी नए उत्पाद का वीडियो, रिव्यू या उपयोग का तरीका कुछ ही घंटों में बड़ी संख्या में संभावित ग्राहकों तक पहुंच सकता है। युवा उपभोक्ता अक्सर किसी उत्पाद को सोशल मीडिया पर देखने के बाद उसके बारे में ऑनलाइन खोज करते हैं और फिर खरीदारी का निर्णय लेते हैं। इस कारण ब्यूटी कंपनियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल प्रचार का माध्यम नहीं बल्कि बिक्री का महत्वपूर्ण चैनल बनते जा रहे हैं।

ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती प्रवृत्ति भी इस बाजार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में ब्यूटी उत्पादों की कुल बिक्री में ऑनलाइन माध्यम की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है, जो वर्ष 2031 तक बढ़कर लगभग 34 प्रतिशत हो सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में ब्यूटी उत्पादों की खरीदारी के लिए उपभोक्ताओं का एक बड़ा हिस्सा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ब्रांड की वेबसाइट और अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही संगठित ऑफलाइन रिटेल की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी। बड़े स्टोर, विशेष ब्यूटी आउटलेट और शॉपिंग सेंटर उपभोक्ताओं को उत्पादों को देखने और आजमाने का अवसर देते हैं। ऐसे में आने वाले वर्षों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ उनका आपसी तालमेल भी देखने को मिल सकता है। क्विक कॉमर्स का विस्तार भी ब्यूटी और ग्रूमिंग बाजार के लिए नया अवसर पैदा कर रहा है। शहरी उपभोक्ता अब रोजमर्रा की जरूरतों के साथ-साथ व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पाद भी कम समय में घर तक मंगाना पसंद कर रहे हैं। शैंपू, फेसवॉश, साबुन, स्किन केयर, हेयर केयर और अन्य ग्रूमिंग उत्पादों की त्वरित डिलीवरी की सुविधा खरीदारी के अनुभव को बदल सकती है। इससे ब्यूटी उत्पादों की खरीदारी अधिक सुविधाजनक और तत्काल जरूरत आधारित हो सकती है। बाजार के विस्तार के साथ नए ब्रांडों के लिए भी अवसर बढ़ने की संभावना है। डिजिटल विज्ञापन, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की उपलब्धता ने छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए ब्यूटी क्षेत्र में प्रवेश करना अपेक्षाकृत आसान बनाया है। पहले किसी नए ब्रांड को बाजार में जगह बनाने के लिए बड़े स्तर पर वितरण नेटवर्क और भारी निवेश की आवश्यकता होती थी, लेकिन डिजिटल माध्यमों ने इस प्रक्रिया को काफी बदल दिया है।

अब कोई नया ब्रांड सीमित स्तर पर उत्पाद तैयार करके सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकता है। यदि उत्पाद और ब्रांड की पहचान उपभोक्ताओं को पसंद आती है तो वह अपेक्षाकृत कम समय में बड़े बाजार तक पहुंच सकता है। इस वजह से आने वाले वर्षों में ब्यूटी और पर्सनल केयर क्षेत्र में नए भारतीय ब्रांडों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

हालांकि बाजार के तेजी से बढ़ने के साथ कंपनियों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। केवल बिक्री बढ़ाना किसी ब्रांड की सफलता की गारंटी नहीं होगी। कंपनियों को ग्राहकों को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने, उत्पाद की गुणवत्ता कायम रखने, विज्ञापन पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करने और मुनाफे को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देना होगा। डिजिटल माध्यमों पर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मार्केटिंग लागत भी बढ़ सकती है। उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता कंपनियों के लिए एक अलग तरह की चुनौती भी पेश करेगी। आज ग्राहक उत्पाद के पैकेज और विज्ञापन से आगे बढ़कर उसके अंदर मौजूद सामग्री, निर्माण प्रक्रिया, कीमत और वास्तविक उपयोगिता के बारे में जानकारी चाहते हैं।

रूस की 'लाइफलाइन' बना भारत का पेट्रोल, दो महीनों में बढ़ी सप्लाई

नई दिल्ली। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के कारण रूस की कई तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों का संचालन प्रभावित होने से वहां पेट्रोल की घरेलू आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। उत्पादन में आई कमी को पूरा करने के लिए रूस को अब विदेशों से पेट्रोल मंगाने पर निर्भर होना पड़ रहा है। इस बदले हुए ऊर्जा समीकरण में भारत रूस के लिए पेट्रोल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में तेजी से उभरकर सामने आया है। पिछले दो महीनों के दौरान भारतीय रिफाइनरियों से रूस को पेट्रोल की आपूर्ति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार का एक नया पहलू सामने आया है।

ऊर्जा बाजार पर नजर रखने वाली कंपनी वॉर्टेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में रूस का समुद्री रास्ते से पेट्रोल आयात बढ़कर करीब 1.25 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। पूरे अगस्त महीने में रूस द्वारा समुद्री मार्ग से करीब 4.70 लाख टन पेट्रोल आयात किए जाने का अनुमान है। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों ने पिछले दो महीनों में रूस को लगभग 10 लाख बैरल पेट्रोल भेजा है। इस आपूर्ति में गुजरात के वडिनार स्थित रिफाइनरी का महत्वपूर्ण योगदान बताया जा रहा है।

रूस के लिए भारत से आने वाला पेट्रोल ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो गया है, जब यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने उसकी घरेलू रिफाइनिंग क्षमता को प्रभावित किया है। रूस की कई रिफाइनरियों को हाल के हमलों में नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। इसके चलते कुछ अवधि में रूस के घरेलू पेट्रोल उत्पादन में करीब 70 प्रतिशत तक की गिरावट आने की बात कही गई है। उत्पादन घटने और घरेलू मांग बनी रहने के कारण रूस को पेट्रोल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए विदेशी आपूर्ति का सहारा लेना पड़ रहा है।

भारत की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भारत के पास बड़ी रिफाइनिंग क्षमता है और वह कच्चे तेल को विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों में बदलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत वैश्विक तेल व्यापार में एक महत्वपूर्ण रिफाइनिंग केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। ऐसे में जब रूस को अचानक अतिरिक्त पेट्रोल की जरूरत पड़ी, तो भारतीय रिफाइनरियों से होने वाली आपूर्ति उसके लिए उपयोगी साबित हो रही है।

भारत और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार का समीकरण वर्ष 2022 के बाद काफी बदल गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल पर कई तरह के प्रतिबंध और मूल्य सीमा जैसी व्यवस्थाएं लागू किए जाने के बीच भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद शुरू की। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल को खरीदकर उसे घरेलू जरूरतों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों में बदलने का काम किया है। आंकड़ों के अनुसार, जून और जुलाई के दौरान भारत ने प्रतिदिन 26 लाख बैरल से अधिक रूसी कच्चा तेल खरीदा। इसी वजह से यह संभावना भी जताई जा रही है कि रूस को निर्यात किए गए पेट्रोल का कुछ हिस्सा रूसी कच्चे तेल से भारतीय रिफाइनरियों में तैयार किया गया हो। हालांकि किसी विशेष खेप में इस्तेमाल किए गए कच्चे तेल का स्रोत अलग-अलग हो सकता है और हर पेट्रोल कार्गो को सीधे रूसी कच्चे तेल से जोड़ना उचित नहीं होगा।

रूस में पेट्रोल संकट की स्थिति केवल रिफाइनरियों पर हुए हमलों तक सीमित नहीं है। उत्पादन प्रभावित होने के साथ घरेलू बाजार में पेट्रोल की उपलब्धता बनाए रखना भी वहां की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ने पर रूस ने घरेलू पेट्रोल बाजार को स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें पेट्रोल की बिक्री से जुड़े प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण जैसे उपाय शामिल हैं।

रूस ने पेट्रोल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और संभावित कमी के कारण कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को नियंत्रित करना है। इसके बावजूद घरेलू उत्पादन में आई कमी को देखते हुए रूस को विदेशी बाजारों से पेट्रोल आयात करना पड़ रहा है। भारत के अलावा तुर्की और मोरक्को भी रूस को पेट्रोल की आपूर्ति करने वाले देशों में शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय रिफाइनरियों से होने वाली आपूर्ति ने इस समय खासा ध्यान आकर्षित किया है। भारत की विशाल रिफाइनिंग क्षमता, समुद्री व्यापार के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों की मजबूत मौजूदगी इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण हैं।

रूस के पेट्रोल आयात में वृद्धि वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। आमतौर पर रूस दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों और रिफाइनिंग क्षमता वाले देशों में शामिल है। ऐसे में उसी देश को अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए बड़ी मात्रा में पेट्रोल आयात करना पड़ रहा है, तो यह वहां की ऊर्जा अवसंरचना पर पड़े दबाव को दर्शाता है।

यूक्रेन की ओर से रूसी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किए जा रहे ड्रोन हमलों का उद्देश्य रूस की ईंधन उत्पादन और आपूर्ति क्षमता को प्रभावित करना बताया जाता है। रिफाइनरियों पर हमलों के कारण उत्पादन प्रक्रिया बाधित होने से इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल जैसे तैयार ईंधन की उपलब्धता पर पड़ सकता है। रूस के लिए चुनौती यह है कि वह एक तरफ अपनी ऊर्जा अवसंरचना को सुरक्षित रखे और दूसरी तरफ घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखे।

भारत के लिए यह स्थिति उसके रिफाइनिंग क्षेत्र की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी रेखांकित करती है। भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक होने के बावजूद अपनी रिफाइनिंग क्षमता के कारण तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम है। भारतीय रिफाइनरियां अलग-अलग स्रोतों से कच्चा तेल लेकर बाजार की मांग के अनुसार पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करती हैं। इससे भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में केवल कच्चे तेल के खरीदार के बजाय एक महत्वपूर्ण रिफाइंड उत्पाद आपूर्तिकर्ता के रूप में भी जगह मिली है। रूस को पेट्रोल की बढ़ती आपूर्ति दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंधों में एक नया आयाम जोड़ती है। पहले जहां भारत और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार की चर्चा मुख्य रूप से कच्चे तेल की खरीद को लेकर होती थी, वहीं अब तैयार पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही भी चर्चा में आ रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में बदलती परिस्थितियों के बीच दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध नए रूप ले रहे हैं।

सितंबर में सोने-चांदी की चमक पर मंडराएंगे कई जोखिम, अमेरिकी रोजगार आंकड़ों और ईरान तनाव से बढ़ सकता है उतार-चढ़ाव

नई दिल्ली। सितंबर का महीना सोने और चांदी के निवेशकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अमेरिकी रोजगार आंकड़ों, फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के संकेतों और अमेरिका-ईरान तनाव जैसे वैश्विक घटनाक्रमों के बीच अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सर्राफा बाजार में कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में निवेशकों को केवल सोने-चांदी की मौजूदा कीमतों पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों और दुनिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव पर भी नजर रखनी होगी।

सितंबर की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब पिछले सप्ताह सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलिवरी वाला सोना वायदा सप्ताह के दौरान 6,157 रुपये यानी करीब 3.8 प्रतिशत टूटकर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसी तरह सितंबर अनुबंध वाली चांदी की कीमत में भी तेज गिरावट रही। चांदी 9,893 रुपये यानी करीब चार प्रतिशत गिरकर 2.36 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

इस गिरावट के बाद अब बाजार की नजर इस बात पर है कि सितंबर में सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा संकेत अमेरिका से आने वाले रोजगार आंकड़ों से मिल सकता है। गैर-कृषि पेरोल, बेरोजगारी दर और एडीपी रोजगार जैसे आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति का संकेत देते हैं। इन आंकड़ों से यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों को लेकर किस तरह का रुख अपना सकता है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक जतिन त्रिवेदी के मुताबिक आगामी सप्ताह बाजार के लिए काफी उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। निवेशक सितंबर में फेडरल रिजर्व की संभावित नीति दिशा को लेकर संकेत तलाश रहे हैं। यदि अमेरिकी आर्थिक आंकड़े कमजोर आते हैं और ब्याज दरों में नरमी

की उम्मीद मजबूत होती है, तो सोने जैसी गैर-ब्याज वाली संपत्तियों को समर्थन मिल सकता है। इसके विपरीत मजबूत रोजगार आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत दे सकते हैं और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर होने पर सोने की कीमतों पर दबाव बन सकता है।

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रणव मेर के अनुसार नए महीने में बाजार की खास नजर गैर-कृषि पेरोल, बेरोजगारी और एडीपी रोजगार आंकड़ों पर रहेगी। इन आंकड़ों का असर केवल अमेरिकी बाजार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि डॉलर, बॉन्ड यील्ड और वैश्विक कमोडिटी बाजारों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि सोने और चांदी के निवेशक अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों को बेहद सावधानी से देख रहे हैं।

सोने की कीमतों के लिए अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों की दिशा विशेष महत्व रखती है। आम तौर पर जब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ती है तो निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ सकता है। सोना ब्याज नहीं देता, इसलिए कम ब्याज दरों के माहौल में इसकी तुलनात्मक आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी ओर, यदि अमेरिकी ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने के संकेत मिलते हैं तो डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड को मजबूती मिल सकती है, जिससे सोने पर दबाव बन सकता है।

सितंबर में केवल अमेरिकी आर्थिक आंकड़े ही सर्राफा बाजार की दिशा तय नहीं करेंगे। अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े घटनाक्रम भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर वैश्विक महंगाई के अनुमान पर पड़ सकता है और इससे प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति प्रभावित हो सकती है।

भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने पर सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में भी समर्थन मिल सकता है। दुनिया के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में संघर्ष या अस्थिरता बढ़ने पर निवेशक अक्सर जोखिम वाली परिसंपत्तियों से पैसा निकालकर अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले विकल्पों की ओर रुख करते हैं। ऐसे समय में सोने की मांग बढ़ सकती है। हालांकि दूसरी तरफ यदि तनाव कम होता है और डॉलर मजबूत रहता है, तो सोने पर दबाव भी देखने को मिल सकता है।

चांदी के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि इसका इस्तेमाल निवेश के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर होता है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में चांदी की मांग रहती है। इसलिए वैश्विक औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े आंकड़े भी चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत मिलते हैं तो औद्योगिक मांग को लेकर चिंता बढ़ सकती है, जबकि आर्थिक गतिविधियों में सुधार चांदी को समर्थन दे सकता है।

भारत में सोने-चांदी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के अलावा रुपये की विनिमय दर का भी असर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर में कारोबार करता है। ऐसे में डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आने पर भारत में आयातित सोने की लागत बढ़ सकती है और घरेलू कीमतों पर इसका असर दिखाई दे सकता है। वहीं रुपये में मजबूती होने पर घरेलू कीमतों को कुछ राहत मिल सकती है।

आने वाले महीने में भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के पीएमआई आंकड़े भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इन आंकड़ों से देश की आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर सामने आती है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के पीएमआई आंकड़ों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। आर्थिक गतिविधियों में तेजी या कमजोरी के संकेत कमोडिटी बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं।

पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में करीब तीन से चार प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में सितंबर में बाजार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हालिया गिरावट के बाद दोनों धातुओं में फिर खरीदारी लौटती है या नहीं। यदि अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद मजबूत होती है और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो सोने को दोहरा समर्थन मिल सकता है। वहीं मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़े और ऊंची ब्याज दरों की संभावना कीमतों में और दबाव पैदा कर सकती है।

कुल मिलाकर सितंबर में सोना-चांदी बाजार कई बड़े वैश्विक संकेतों के बीच कारोबार करता नजर आ सकता है। अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट, फेडरल रिजर्व का रुख, डॉलर की चाल, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिका-ईरान तनाव और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के पीएमआई आंकड़े बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक होंगे। ऐसे माहौल में निवेशकों को अचानक होने वाली तेजी या गिरावट के बजाय वैश्विक घटनाक्रम और आर्थिक आंकड़ों को समझकर ही निर्णय लेने की जरूरत होगी।

पश्चिम बंगाल से संबंधित प्रश्न: चुनाव आयोग के समक्ष प्रश्न: 91% अपीलों में मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े गए

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

एक लोकतांत्रिक देश में, चुनावों की विश्वसनीयता सबसे पहले मतदाता सूची से शुरू होती है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि मतदाता सूची में एक भी गलत नाम न रहे और किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम न छूटे। लेकिन पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के गहन संशोधन (एसआईआर) से संबंधित जो जानकारी सामने आई है, उससे चुनाव आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल उठते हैं।

अब सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी चौंकाने वाली है। अब तक निपटाए गए 82,762 अपीलों में से 75,443 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में फिर से जोड़ दिए गए हैं। जबकि केवल 7,339 नाम छूट गए हैं। इसका मतलब है कि निपटाए गए अपीलों में 91 प्रतिशत से अधिक लोगों को राहत मिली है।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अपील के बाद इतनी बड़ी संख्या में नाम सही पाए जाते हैं, तो शुरुआती प्रक्रिया में गलती कहां हुई? क्या मतदाताओं के दस्तावेजों और तथ्यों की पर्याप्त जांच किए बिना संदेह के आधार पर नामों को खारिज कर दिया गया था? फिर क्या एसआईआर प्रक्रिया ही इतनी जटिल थी कि आम नागरिक के लिए अपने मतदान के अधिकार को साबित करना मुश्किल हो जाए?

सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितने नाम हटाए गए और कितने वापस जोड़े गए। असली सवाल यह है कि जिन लोगों के नाम गलती से हटा दिए गए थे, उनमें से कितनों को चुनाव के दिन वोट डालने का मौका मिला? अगर किसी असली मतदाता का नाम मतदान से पहले सूची से गायब हो जाता है और चुनाव के बाद अपील में सही साबित होता है, तो उसे हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी और उसके मतदान के अधिकार का क्या होगा? इसलिए, लोकतंत्र में चुनावों की निष्पक्षता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मतदान प्रतिशत। यदि फर्जी मतदाताओं को रोकने के प्रयास में वास्तविक मतदाताओं को मतदान से वंचित किया जाता है, तो सुधार प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में जानकारी जुटा रहा है और एसआईआर के बाद दायर अपीलों और मतदाता सूची में किए गए बदलावों पर नजर रख रहा है।

एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से बिना सील तोड़े ही कागज़ लीक हो गया, 11 हज़ार रुपये के सौदे में हाई-टेक घोटाला उजागर हुआ

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित भारती कृषि महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया ने बिना किसी कवर या पैकेट की सील तोड़े परीक्षा की पर्ची को रिकॉर्ड करके लीक कर दिया। इस हाई-टेक लीक के लिए आरोपी ने एंडोस्कोपिक कैमरा और चिकित्सा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली सुई का इस्तेमाल किया। एंडोस्कोपिक कैमरा एक बहुत ही महीन, पतली और लचीली ट्यूब जैसी डिवाइस होती है। इसमें एक छोटा एचडी कैमरा और इसके सिरे पर एलईडी लाइट लगी होती है। डॉक्टर इसका इस्तेमाल शरीर के आंतरिक अंगों जैसे पेट या गले की जांच के लिए करते हैं। इस कैमरे का तार

इतना पतला होता है कि इसे आसानी से किसी भी छोटे छेद या पतले पाइप में डाला जा सकता है। कैमरे से जुड़ी लाइट अंदर के अंधेरे को दूर करती है और लाइव वीडियो स्क्रीन पर दिखने लगता है। बीएससी के दूसरे वर्ष के कृषि कीट विज्ञान विषय की सीलबंद पर्ची घर ले जाने के बाद आरोपी प्रोफेसर ने एक बड़ी चालाकी अपनाई। प्रोफेसर ने सबसे पहले सीलबंद कवर के निचले हिस्से में बिना उसे नुकसान पहुंचाए एक महीन सुई या नुकीली वस्तु से एक छोटा सा छेद किया। उस छोटे से छेद के ज़रिए उसने एंडोस्कोपिक कैमरे की पतली सी केबल को कवर के अंदर डाला। कैमरे के सामने की रोशनी ने कवर के अंदर के अंधेरे को दूर कर दिया और अंदर रखे कागज़ के पन्ने साफ़ दिखाई देने लगे।

कैमरे से लाइव फुटेज देखने के बाद, प्रोफेसर ने एक कागज पर हाथ से लगभग 15 प्रश्न लिखे। इसके बाद उन्होंने यह कागज एक छात्र को 11,000 रुपये में बेच दिया। यहीं से यह व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। AGCH-221 की परीक्षा 20 अगस्त की सुबह होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से लगभग दो घंटे पहले सूचना मिली कि प्रश्न पत्र कवर्धा कृषि महाविद्यालय के ईमेल पर लीक हो गया है।

मामला सामने आते ही विश्वविद्यालय ने 28 कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द कर दीं। पुलिस और साइबर टीम ने आरोपी प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से सभी उपकरण जब्त कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।